● वर्ष-5
● अंक-219
रायपुर, शुक्रवार
01 मई 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार



पेज-6› चेहरे को चमकाएं....

विधानसभा का विशेष सत्र

महिला आरक्षण पर संकल्प पारित

डबल इंजन सरकार में मातृशक्ति को मिला है सम्मान और स्वाभिमान : साय

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में संकल्प प्रस्तुत करते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान, समग्र विकास और सशक्तिकरण के लिए संसद और सभी विधानसभाओं में उनके लिए एक तिहाई आरक्षण सुनिश्चित किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि यह पहल न केवल लोकतांत्रिक संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुदृढ़ करेगी, बल्कि समाज में समान अवसर और संतुलित प्रतिनिधित्व की दिशा में भी एक नई ऊर्जा प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रकार के प्रयासों से देश की आधी आबादी को निर्णय प्रक्रिया में सशक्त भूमिका मिलेगी और विकास अधिक समावेशी एवं प्रभावी बनेगा।



मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की यह पावन धरती माता शबरी, मां दंतेश्वरी और मां महामाया की भूमि है, जहां नारी को सदैव शक्ति के रूप में सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी केवल सम्मान की पात्र नहीं, बल्कि सृजन और शक्ति की आधारशिला है। नवरात्रि में जिस शक्ति की हम पूजा करते हैं, वही शक्ति समाज में मातृरूप में विद्यमान है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारे शास्त्रों में वर्णित या देवी सर्वभूतेषु मातृ-रूपेण संस्थिता केवल एक श्लोक नहीं, बल्कि भारतीय जीवन-दर्शन का मूल तत्व है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की धरती पर भक्त माता कर्मा, तीजन बाई, उषा बारले जैसी विभूतियों ने अपनी प्रतिभा और समर्पण से प्रदेश की पहचान को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाया है। साथ ही, रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती और अवंती बाई जैसी वीरांगनाओं के योगदान को भी उन्होंने प्रेरणास्रोत बताया। आधुनिक युग में कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स जैसी महिलाओं ने देश का गौरव वैश्विक स्तर पर बढ़ाया है।

सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस

छत्तीसगढ़ विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में 33% महिला आरक्षण को लेकर शासकीय संकल्प पारित किया गया। सत्र की शुरुआत से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली।



चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक अनिला भेड़िया ने महिला आरक्षण बिल को चुनावी झुनझुना बताया। वहीं डिप्टी सीएम साव ने कांग्रेस पर वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। दोनों पक्षों ने महिलाओं को अवसर देने के मुद्दे पर एक-दूसरे को घेरा। महिला प्रतिनिधित्व को लेकर भी आंकड़ों पर बहस हुई। दरअसल भाजपा के 54 में 8 महिला विधायक हैं। वहीं कांग्रेस के 35 में से 11 महिला विधायक हैं।

नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा लाया गया समान प्रस्ताव (अशासकीय संकल्प) स्वीकार नहीं किया गया। विपक्ष का कहना है कि मौजूदा सीटों के भीतर ही 33% आरक्षण लागू किया जा सकता है। सरकार महिलाओं को भ्रमित कर रही है। पहले निंदा प्रस्ताव की बात कही गई, अब संकल्प लाया गया।

विधानसभा अध्यक्ष का जवाब

विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने स्पष्ट किया कि विपक्ष का प्रस्ताव इसलिए स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि विशेष सत्र का एजेंडा पहले से तय था और यह सत्र सरकारी कार्य के लिए बुलाया गया था।

विधायकों के बयान

आजादी के बाद से 5 दशक कांग्रेस ने राज किया। इस दौरान महिलाओं के लिए काम क्यों नहीं किया गया

– किरण सिंह देव, बीजेपी विधायक

छत्तीसगढ़ देश का दूसरा ऐसा राज्य है जहां हमारी सरकार ने आरक्षण दिया, महिलाओं को संस्थाओं में 50 फीसदी आरक्षण दिया गया

– अजय चंद्राकर, बीजेपी विधायक

2011 में कांग्रेस ने जनगणना कराई थी। 2022 में बीजेपी सरकार को करना था तब क्यों नहीं किया गया– कवासी लखमा, कांग्रेस

जब पूरे देश में चुनाव आ रहे तो मोदी जी अचानक 33 फीसदी आरक्षण लाने की घोषणा करते हैं, महिलाएं समझदार हैं बहकाइए मत।

– संगीता सिन्हा, कांग्रेस

500 से ज्यादा महिला की मौजूदगी

इस विशेष सत्र में प्रदेश भर से 500 से अधिक महिला जनप्रतिनिधि शामिल हुईं, जिससे सत्र का महत्व और बढ़ गया। महिला सुरक्षा, अधिकार और राजनीतिक भागीदारी जैसे मुद्दों पर जोरदार चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने कई महिलाओं से मुलाकात की और कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं।

प्रदेश में आज से सुशासन तिहार

■ समाधान शिविर में जनता की शिकायतों का होगा त्वरित निराकरण

रायपुर। छत्तीसगढ़ में आम नागरिकों की समस्याओं के त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए सुशासन तिहार 2026 की शुरुआत आज से होने जा रही है। यह अभियान 10 जून 2026 तक प्रदेशभर में चलाया जाएगा, जिसके तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर जन समस्या निवारण शिविर आयोजित किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जन शिकायतों का समयबद्ध निराकरण ही सुशासन की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि आमजन को पारदर्शी, सरल और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

पहले चरण में लंबित मामलों के निराकरण पर जोर

अभियान के पूर्व चरण में ही कलेक्टरों को निर्देशित किया गया है कि 30 अप्रैल तक सभी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित करें। इसमें— नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन जैसे राजस्व प्रकरण, मनरेगा के लंबित मजदूरी भुगतान, हितग्राहीमूलक योजनाओं के लंबित भुगतान, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, बिजली, ट्रांसफार्मर और पेयजल (हैंडपंप) समस्याएं के त्वरित निराकरण पर विशेष ध्यान रखा जाएगा, साथ ही पात्र हितग्राहियों को उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत और सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ दिलाने के निर्देश भी दिए गए हैं।

समाधान शिविर

सुशासन तिहार के तहत 1 मई से 10 जून तक लगेंगे शिविर, ग्रामीण क्षेत्रों में 15- 20 ग्राम पंचायतों के समूह में शिविर, शहरी क्षेत्रों में वार्ड क्लस्टर आधारित आयोजन, मौके पर ही आवेदन स्वीकार और लाभ वितरण, अधिकतम एक माह में आवेदनों का निराकरण, शिविरों में शासन की योजनाओं के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई जाएगी और प्रत्येक आवेदक को उसके आवेदन की स्थिति की जानकारी दी जाएगी।

सीधा संवाद

अभियान के दौरान मंत्रीगण, सांसद, विधायक, मुख्य सचिव और प्रभारी सचिव समय-समय पर शिविरों में पहुंचकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे और आम नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित करेंगे।

सीएम करेंगे औचक निरीक्षण और समीक्षा

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय स्वयं विभिन्न जिलों का दौरा कर विकास कार्यों का औचक निरीक्षण, हितग्राहियों से सीधा फीडबैक,जिला स्तर पर समीक्षा बैठकें करेंगे, निरीक्षण के बाद वे प्रेसवार्ता के माध्यम से जानकारी साझा करेंगे और नागरिकों व सामाजिक संगठनों से सुझाव भी लेंगे।

व्यापक प्रचार से बनेगा जन आंदोलन

जनसम्पर्क विभाग और जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि अभियान के व्यापक प्रचार-प्रसार के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए। डिजिटल, प्रिंट और स्थानीय माध्यमों के जरिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जाएगा।

स्ट्रांग रूम पूरी तरह सुरक्षितः चुनाव आयोग

नई दिल्ली/कोलकाता। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि कगुड़ीराम अनुशीलन केंद्र के सभी सात एसी स्ट्रांग रूम मतदान के बाद उम्मीदवारों और पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में ठीक से सील किए गए हैं और पूरी तरह सुरक्षित हैं। ईवीएम और मतपत्रों दोनों की सुरक्षा व्यवस्था पूरी पारदर्शिता के साथ की गई है और इसकी जानकारी सभी संबंधित अधिकारियों व राजनीतिक दलों को पहले ही दी जा चुकी है। अधिकारियों ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को लेकर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि कगुड़ीराम अनुशीलन केंद्र में कुल सात एसी स्ट्रांग रूम हैं। सभी स्ट्रांग रूम को मतदान खत्म होने के बाद उम्मीदवारों, चुनाव एजेंटों और सामान्य पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में ठीक से बंद और सील कर दिया गया था।

बंगाल में खिलेगा कमल, 192 सीटें मिलने का अनुमान

नईदिल्ली। पश्चिम बंगाल में हवा का रुख बदलता दिख रहा है। गुरुवार को आए टुडेज़ चाणक्य के एग्जिट पोल ने राज्य के राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़े बदलाव का संकेत दिया है, जिसमें बीजेपी को 192+ सीटों के साथ स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है। इसके विपरीत, टीएमसी को 100+ सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य दलों को केवल 2 सीटें मिलने की संभावना है। यदि ये अनुमान सही साबित होते हैं, तो यह पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा मोड़ होगा, जिससे राज्य में टीएमसी का 15 साल पुराना वर्चस्व खत्म हो सकता है। ये आंकड़े बीजेपी के पक्ष में समर्थन के मज़बूत एकीकरण की ओर इशारा करते हैं, जो मतदाताओं की पसंद में एक निर्णायक बदलाव का संकेत है। बहुमत का आंकड़ा 147 है। यह ताज़ा अनुमान पाँचवाँ ऐसा एग्जिट पोल है, जो पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बढ़त दिखा रहा है।



2021 के विधानसभा चुनावों में ज़्यादातर एग्जिट पोल्स ने बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़े मुकाबले का अनुमान लगाया था। लेकिन, अंतिम नतीजे इसके बिल्कुल उलट रहे। टीएमसी ने 215 सीटों पर निर्णायक जीत हासिल की, जबकि बीजेपी को 77 सीटें मिलीं और वह मुख्य विपक्षी दल के रूप में उभरी। एग्जिट पोल्स, वोट डाले जाने के बाद मतदाताओं के बीच किए गए सर्वे पर आधारित होते हैं और इनका मकसद जनता के मूड को समझना होता है; हालाँकि, इनके अनुमान हमेशा अंतिम नतीजों से मेल नहीं खाते।

पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को दो चरणों में वोटिंग हुई। इस दौरान केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती थी और 90 प्रतिशत से ज़्यादा वोटिंग दर्ज की गई। बीजेपी ने इस भारी वोटिंग को टीएमसी के 15 साल के शासन के बाद पोरिबोरतोन या बदलाव का संकेत बताया। कई पोल करने वालों ने भी इसी रुझान को दिखाया बीजेपी के लिए सबसे मज़बूत अनुमानों में से एक दिया, जिसमें 150-175 सीटों का अंदाज़ा लगाया गया, जबकि टीएमसी को 118-138 सीटें दी गईं। जिसमें भाजपा के लिए 150-160 सीटें और टीएमसी के लिए 130-140 सीटों का अनुमान लगाया गया।

प्रमुख समाचार

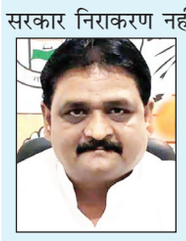
पवन खेड़ा की जमानत याचिका पर असम पुलिस का कड़ा विरोध

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर तीखी बहस हुई। असम पुलिस ने खेड़ा की याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए उन पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी, रिंकी भुइयां सरमा के पासपोर्ट के साथ छेड़छाड़ और जालसाजी करने का गंभीर आरोप लगाया है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चांदुरकर की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पुलिस ने कहा कि खेड़ा ने जो किया वह एक गैर-ज़मानती अपराध है और इस बात की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने दस्तावेज़ों में जालसाज़ी कैसे की। असम पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि खेड़ा ने सरमा की पत्नी पर ये आरोप तब लगाए, जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे। उन्होंने कहा कि खेड़ा ने रिंकी की तस्वीरें दिखाईं और नकली पासपोर्ट पेश किए; जांच में पता चला है कि खेड़ा के पास जो दस्तावेज़ थे, वे नकली थे। मेहता ने कहा कि खेड़ा अपराध की तारीख से ही फरार चल रहे हैं; हालांकि वे वीडियो जारी कर रहे हैं।



20 लाख मीट्रिक टन धान खुले में पड़ा, सूख रहाः शुक्ला

रायपुर। सरकार की लापरवाही के कारण 20 लाख मीट्रिक टन धान संग्रहण केन्द्रों में खुले में पड़ा है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि धान भीषण गर्मी में सुख रहा है, बे-मौसम बारिश से भीग रहा है। 3100 रु. प्रति क्विंटल में खरीदे गए धान का सरकार निराकरण नहीं कर पाई है। भाजपा दावा करती है डबल इंजिन की सरकार का तो केंद्र से बोल कर पूरे खरीदे गए धान से बने चावल को सेन्ट्रल पुल में दे दे, इससे राज्य को करोड़ों का नुकसान भी नहीं होगा, धान का निराकरण का समाधान भी हो जायेगा। धान खुले में पड़ा सुख रहा है, सड़ रहा है, बाद में इसी के आधार पर पूरा धान खराब हो गया बता कर भ्रष्टाचार करेंगे। चूहों पर तोहमत लगाएंगे। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने प्रदेश की विष्णुदेव सरकार के द्वारा छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान से बना पूरा चावल नहीं खरीदा, जिसके चलते राज्य सरकार को किसानों से खरीदे गए धान के निस्तारण की समस्या उत्पन्न हो गई है।



अग्नि-6: पहली हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल का टेस्ट ...



नईदिल्ली रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के चेयरमैन समीर वी. कामत ने कहा कि जिस अग्नि वीआई बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम का बेसब्री से इंतज़ार किया जा रहा है, वह सरकार की मंजूरी मिलते ही आगे बढ़ेगा। एएनआई नेशनल सिक्योरिटी समिट 2.0 में बोलते हुए उन्होंने बताया कि एजेंसी ने सारा शुरुआती काम पूरा कर लिया है और औपचारिक मंजूरी मिलते ही काम शुरू करने के लिए तैयार है। उम्मीद है कि अग्नि वीआई भारत की अग्नि सीरीज़ की सबसे एडवांस्ड मिसाइल बनेगी, जिसकी मारक क्षमता और परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होगी। हालाँकि यह प्रोजेक्ट अभी भी एक पॉलिसी फ़ैसले पर निर्भर है, लेकिन डीआरडीओ की तैयारी से पता चलता है कि भारत अपने रणनीतिक हथियारों के ज़खीरे में एक और बड़े अपग्रेड के लिए कमर कस रहा है। डीआरडीओ प्रमुख ने प्रस्तावित पारंपरिक मिसाइल बल की विकसित हो रही संरचना के बारे में भी बात की और इस बात पर ज़ोर दिया।

9 मई को नेशनल लोक अदालत का होगा आयोजन

रायपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार शनिवार 9 मई 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य में तालुका न्यायालय के स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजित कर राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सुलह समझौता से निराकृत किये जाएंगे। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए इस स्थापना अन्तर्गत विभिन्न थानाओं में पदस्थ पैरालीगल वालिन्टियर्स द्वारा अपने क्षेत्रों में विभिन्न सुदुर अंचलों के गांवों, नगरों, कस्बों में नेशनल लोक अदालत के लाभों के बारे में बताते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर निराकरण हेतु दाण्डिक राजीनामा योग्य प्रकरण, चेक बाउन्स अर्थात् 138 वाले मामले, बैंक रिकवरी अर्थात् प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरण, भरण-पोषण धारा 125 के प्रकरण, परिवार न्यायालय से संबंधित प्रकरण, श्रमिक प्रकरण, जमीन विवाद प्रकरण तथा राजस्व प्रकरणों को नियत किया गया।

ईवीएम स्ट्रांग रुम की खुद करूंगी पहरेदारीः ममता

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी एक निर्णायक जीत की राह पर है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता एक ऐसी सरकार को वापस लाने के लिए तैयार है, जिसकी जड़ें उनके शब्दों में माँ (माता), माटी (भूमि) और मानुष (लोग) की भावना में निहित हैं। ममता ने दावा किया कि चुनाव परिणाम पहले से ही उनकी पार्टी के पक्ष में स्पष्ट हैं। केंद्र सरकार ने अपनी पूरी मशीनरी लगा दी, लेकिन जीत हमारी ही होगी। हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों को लेकर अपने आत्मविश्वास को और मज़बूत करते हुए उन्होंने कहा कि हम 2026 में 226 से ज़्यादा सीटें जीतेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने विधानसभा चुनावों के एग्जिट पोल के अनुमानों की कड़ी आलोचना की और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि उसने तृणमूल कार्यकर्ताओं में घबराहट पैदा करने के लिए आंकड़ों में हेरफेर किया है।



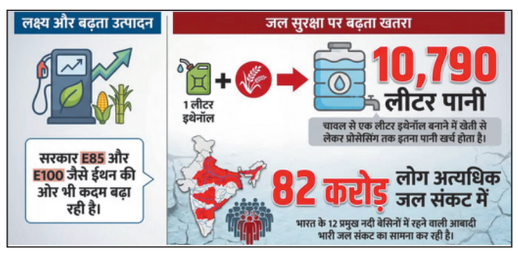
एक लीटर इथेनॉल उत्पादन निगल रहा दस हजार लीटर पानी

नईदिल्ली। भारत सरकार इथेनॉल ब्लेंडिंग को ऊर्जा सुरक्षा और प्रदूषण कम करने के बड़े समाधान के तौर पर पेश कर रही है। पेट्रोल में इथेनॉल मिलाकर विदेशी तेल पर निर्भरता घटाने और किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने साल 2025 में ही पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने (ई20) का बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है।

अब सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटी॥) ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन का एक ड्राफ्ट जारी किया है। इस नए ड्राफ्ट का उद्देश्य ई 85 और ई100 जैसे आधुनिक फ्यूल को शामिल करना है। ई 85 फ्यूल का अर्थ है एक ऐसा मिश्रण जिसमें 85% इथेनॉल और सिर्फ 15%पेट्रोल होगा। वहीं, भविष्य की सबसे बड़ी तैयारी ई100 फ्यूल को लेकर है, जिसका सीधा मतलब 100% शुद्ध इथेनॉल है। इसके लिए उत्पादन क्षमता तेजी से बढ़ाई जा रही है। गन्ना, चावल और मक्का जैसे कच्चे माल से बड़े पैमाने पर इथेनॉल तैयार किया जा रहा है, वहीं सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां इसे पेट्रोल में मिलाकर बाजार में बेच रही हैं।

लेकिन इस पूरी नीति के बीच एक बड़ा सवाल पानी को लेकर खड़ा हो रहा है। इथेनॉल उत्पादन की प्रक्रिया में भारी मात्रा में पानी की जरूरत होती है। खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा के मुताबिक, चावल से एक लीटर इथेनॉल बनाने में करीब 10,790 लीटर पानी खर्च होता है। इस आंकड़े में खेती के दौरान सिंचाई से लेकर प्रोसेसिंग तक की पूरी जल खपत शामिल है। ऐसे में जिस ईंधन को पर्यावरण के अनुकूल बताया जा रहा है, वह वास्तव में जल संसाधनों पर बड़ा दबाव डाल सकता है।

स्थिति इसलिए और गंभीर हो जाती है क्योंकि इथेनॉल जिन फसलों से बनता है, वे पहले से ही देश में सबसे ज्यादा पानी लेने वाली फसलें हैं। गन्ना, चावल और मक्का भारत के सीमित जल संसाधनों का बड़ा हिस्सा खपत करते हैं। अब इन्हीं फसलों को ईंधन उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करने से जल संकट और गहरा होने की आशंका बढ़ गई है।



सरकार ने इथेनॉल उत्पादन बढ़ाने के लिए खाद्य नीति में भी बदलाव शुरू कर दिया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत दिए जाने वाले अनाज में टूटे हुए चावल की हिस्सेदारी 25 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत करने का प्रस्ताव है। इस कदम से हर साल लगभग 90 लाख टन टूटे हुए चावल इथेनॉल उत्पादन के लिए उपलब्ध हो सकेंगे। अतिरिक्त चावल को नीलामी के जरिए इथेनॉल कंपनियों और अन्य उद्योगों को दिया जाएगा। आगे की योजना में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के स्टॉक से साबुत चावल की सप्लाई बंद कर टूटे हुए चावल को स्थायी कच्चा माल बनाने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि इथेनॉल उद्योग को सालभर आपूर्ति मिलती रहे।

इथेनॉल उत्पादन क्षमता में भी तेजी से वृद्धि हुई है। जहां 2013-14 में उत्पादन क्षमता करीब 420 करोड़ लीटर थी, वहीं अब यह बढ़कर लगभग 2000 करोड़ लीटर तक पहुंच गई है। मौजूदा समय में करीब 40 प्रतिशत इथेनॉल अनाज आधारित स्रोतों, खासकर मक्का से तैयार किया जा रहा है। सरकार मक्का उत्पादन बढ़ाने के लिए नई किस्मों और क्लस्टर आधारित खेती को भी बढ़ावा दे रही है।

नीति आयोग की रिपोर्ट

वहीं नीति आयोग की 2019 की %समग्र जल प्रबंधन सूचकांक रिपोर्ट% देश में जल संकट की गंभीर तस्वीर पेश करती है। रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक भारत की शहरी आबादी 60 करोड़ तक पहुंच जाएगी और घरेलू पानी की मांग दोगुनी हो सकती है। अनुमान है कि उस समय पानी की मांग और आपूर्ति के बीच लगभग 50 बिलियन क्यूबिक मीटर का अंतर होगा। भारत के 12 प्रमुख नदी बेसिनों में करीब 82 करोड़ लोग उच्च से अत्यधिक जल संकट की स्थिति में जी रहे हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा जल संकट झेल रहे 20 बड़े शहरों में से पांच भारत में हैं और कई शहरों में अभी भी 24 घंटे पानी की आपूर्ति उपलब्ध नहीं है।

नक्सल आत्मसमर्पण के बाद माओवादी खेमे में घमासान

एनसीसीस ने प्रेस नोट जारी कर वेणुगोपाल देवजी को बताया 'गद्दार'

जगदलपुर। नक्सल मोर्चे से बड़ी खबर सामने आई है, जहां माओवादी संगठन के भीतर आंतरिक टकराव खुलकर सामने आ गया है। नॉर्थ कोऑर्डिनेशन कमेटी (एनसीसी) द्वारा जारी एक प्रेस नोट में आत्मसमर्पण कर चुके शीर्ष माओवादी नेता वेणुगोपाल देवजी पर तीखा हमला किया गया है।


Communist Party Of India (Maoist)
North Coordination Committee (NCC)
Press Release
Date: 17th April, 2026.
Expose the neo-Prachand path of Devji and his likes!
Hold high the red banner of Marxism-Leninism-Maoism!
Bury all the opportunist-liquidationist-revisionist elements!





एनसीसी ने अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा है कि देवजी अब संगठन के लिए गद्दार हैं और उनके आत्मसमर्पण के बाद संगठन का उनसे कोई संबंध नहीं रह गया है। इस बयान के बाद माओवादी खेमे में हलचल और तेज हो गई है। बता दें कि वेणुगोपाल देवजी के आत्मसमर्पण को लेकर संगठन के भीतर लंबे समय से असंतोष की स्थिति बताई जा रही थी। अब एनसीसी के ताजा बयान ने इस विवाद को सार्वजनिक रूप से और बढ़ा दिया है। संगठन ने यह भी कहा है कि उनका संघर्ष अब भी जारी रहेगा और वे सशस्त्र आंदोलन को ही अंतिम रास्ता मानते हैं। प्रेस नोट में एनसीसी ने दोहराया है कि संगठन कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन वह खत्म नहीं हुआ है। बयान में कहा गया है कि वे गोरिल्ला युद्ध के जरिए अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाते रहेंगे और क्रांति को जारी रखेंगे। देवजी द्वारा माओवादी संगठन पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग को भी एनसीसी ने सिरे से खारिज कर दिया है। संगठन ने इसे व्यक्तिगत राय बताते हुए कहा कि यह विचार संगठन की आधिकारिक नीति नहीं है। अपने बयान में एनसीसी ने यह भी दावा किया है कि संगठन के भीतर किसी भी तरह की दरार या मतभेद नहीं हैं और वे पूरी तरह एकजुट हैं।

मोबाइल टावर्स बने माओवाद की ताबूत में अंतिम कील, कनेक्टिविटी बढ़ने पर सिमटा लाल घेरा

बस्तर। बस्तर में बीते 4 दशकों से काबिज रहे माओवादियों के अवैध गढ़ को नेस्तनाबूद करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मोबाइल टावर्स ने निभाई है। माओवादी अंदरूनी क्षेत्रों में सड़क और सरकारी सिस्टम को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ने से रोकते थे। लेकिन पुलिस कैंप के साथ ही मोबाइल नेटवर्क सिस्टम ने माओवादियों तक पुलिस की पहुंच आसान बना दी। माओवादियों के हर गतिविधि की सूचना मोबाइल नेटवर्क के जरिए आसानी से पुलिस को मिल रही थी। जिसकी वजह से माओवादियों की घेराबंदी और लंबे समय तक किसी ठिकाने में



छिपकर रहना उनके लिए मुश्किल हो गया था। मोबाइल नेटवर्क के कारण माओवादियों की लोकेशन आउट होने के साथ ही पुलिस के लिए उनके खिलाफ ऑपरेशन काफी आसान हो गए।छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद 2023 तक बीएसएनएल ने 640 टावर लगाए। निजी कंपनियों के आंकड़ों को देखें तो ये 800 के करीब थे। वजह यह थी कि माओवादी निजी कंपनियों के साथ ही बीएसएनएल के टावरों को अंदरूनी क्षेत्र में लगने देते नहीं थे। क्योंकि उन्हें पता था कि नेटवर्क होने पर मोबाइल का इस्तेमाल कर आसानी से उनकी मुखबिरी की जा सकती है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि मोबाइल कनेक्टिविटी के माध्यम से स्थानीय युवाओं को बाहर की दुनिया से रूबरू कराने के उद्देश्य से विगत समय में काफी बड़ी संख्या में मोबाइल टावरों की स्थापना की गई। सुंदरराज पी के मुताबिक मोबाइल टॉवर से पुलिस को माओवादियों की हर मूवमेंट की जानकारी मिलने लगी। इसलिए 2023 से 25 के बीच माओवादियों को बड़ी आसानी से पुलिस ने समेट दिया और उनके क्षेत्र सीमित हो गए। साल 2026 आते-आते माओवादियों को आत्मसमर्पण या फिर न्यूट्रिलाइज करना आसान हो गया। जिसकी वजह से अब बस्तर से सशस्त्र माओवाद पूरी तरह समाप्त होने की कगार पर पहुंच गया है।बस्तर में माओवाद के खिलाफ हालात तब बदले जब 2023 में पुलिस ने योजनाबद्ध तरीके से फॉरवर्ड बेस कैंप खोलना शुरू किया।

पहली योजना नक्सलियों के क्षेत्रों में कैंप स्थापित करने की थी।

बिल्डर्स अमर इंफ्रा के यहां ईडी का छापा

दुर्ग। अमर बिल्डर्स (अमर इंफ्रा) के संचालक चतुर्भुज राठी की महेश कॉलोनी स्थित साकेत निवास और पुलगांव नाला स्थित ऑफिस अमर बिल्डर्स (अमर इंफ्रा)में ईडी की टीम ने छापा मारा है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक टीम में करीब सात अधिकारी हैं, जो दो कार से सुबह करीब छह बजे के आसपास पहुंचे.दस्तावेजों,कंप्यूटर सहित अन्य माध्यमों की जांच की जा रही है।

इस ग्रुप के 6 से अधिक बड़े फर्म संचालित हैं। चतुर्भुज राठी के घर और ऑफिस में दोनों टीम की अलग अलग कार्रवाई चल रही है. घर व ऑफिस के बाहर सुरक्षा के लिहाज से पुलिस जवान



तैनात किए गए हैं .किसी भी आदमी को भीतर जाने नहीं दिया जा रहा है. जानकारी के मुताबिक ईडी की टीम पहुंची उस दौरान चतुर्भुज राठी घर पर थे .खबर है कि भारतमाला परियोजना के गड़बड़ी में इनका नाम भी आया है।

सरगुजा की इलीसीबा और अनामिका खेलेंगी नेशनल गेम

सरगुजा। अंबिकापुर जिले में खेल सुविधाएं बढ़ने से उसे परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। भारत देश के खिलाड़ियों की फौज में सरगुजा क्षेत्र के खिलाड़ियों का भी अब नाम आने लगा है। पिछड़ेपन के लिए चर्चित सरगुजा में खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे ज्यादा संख्या लड़कियों की है।जो लगातार राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर छत्तीसगढ़ और सरगुजा का नाम रोशन कर रही हैं। एक बार फिर सरगुजा की दो बेटियों का चयन छत्तीसगढ़ राज्य की टीम में हुआ है ये टीम इंडिया लेबल पर प्रदर्शन करेगी। अंबिकापुर की रहने वाली अनामिका चौबे और जशपुर की रहने वाली इलीसीबा



तिर्की का चयन बॉस्केटबाल की नेशनल टीम में हुआ है। इलीसीबा तिर्की एक गरीब आदिवासी परिवार से आती हैं। उनके पिता राज मिस्त्री का काम करते हैं। आर्थिक स्थिति ठीक तो नहीं है फिर भी पिता पढ़ाई और अंबिकापुर में रहने का खर्च उठाते हैं।जबकि इलीसीबा का खेल निखारने में कोच राजेश सिंह मदद करते हैं। इलीसीबा और अनामिका चौबे दोनों ही अपने पहले नेशनल में गोल्ड और दूसरे नेशनल में ब्रॉन्ज मेडल पा चुकी हैं। अब एक बार फिर अपने राज्य के लिए प्रदर्शन करने को तैयार हैं। जिला बास्केटबॉल संघ से दो खिलाड़ियों का चयन छत्तीसगढ़ राज्य टीम में हुआ है।चयनित खिलाड़ियों में इलीसीबा तिर्की और अनामिका चौबे शामिल हैं, जो आगामी ऑल इंडिया ओपन बास्केटबॉल टूर्नामेंट 2026 बनारस में राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह टूर्नामेंट देशभर के श्रेष्ठ खिलाड़ियों को एक मंच प्रदान करता है, जिसमें सरगुजा के खिलाड़ियों को मौका मिलना जिले के खेल विकास के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

डोंगरगढ़ में अवैध शराब नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई



- **एमपी निर्मित व्हिस्की जब्त, री-पैकिंग का खुला खेल, मुख्य आरोपी फरार**

डोंगरगढ़। जिले में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। ग्राम कातलवाही में दबिश देकर भारी मात्रा में मध्य प्रदेश निर्मित विदेशी शराब और पैकिंग सामग्री जब्त की है। यह कार्रवाई देर शाम शुरू होकर रात करीब 11 बजे तक चली।

बता दें कि प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी अभिषेक तिवारी के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में टीम ने बिना सर्च वारंट के भिखारी निषाद के बाड़ी स्थित मकान पर छापा मारा। सूचना के आधार पर की गई इस दबिश में नाले किनारे अवैध भंडारण और शराब की हेराफेरी की पुष्टि हुई।

तलाशी के दौरान कुल 243 बल्क लीटर अवैध व्हिस्की बरामद की गई, जिसमें 264 बोतल (750 एमएल) बॉम्बे व्हिस्की और 250 पाव (180 एमएल) गोवा व्हिस्की शामिल हैं। इसके अलावा बड़ी मात्रा में पैकिंग सामग्री भी मिली। कार्रवाई में सिर्फ शराब ही नहीं, बल्कि नकली पैकेजिंग का पूरा नेटवर्क सामने आया। मौके से 200 खाली बोतलें (MP लेबल), 500 खाली पाव (छत्तीसगढ़ लेबल), 220 टूटे ढक्कन और 715 साबुत ढक्कन बरामद किए गए। इससे स्पष्ट है कि यहां अवैध री-पैकिंग और सप्लाई का संगठित कारोबार चल रहा था। छापेमारी के दौरान मुख्य आरोपी चंद्रकांत सेन उर्फ सोनू मौके से फरार हो गया। आबकारी विभाग ने उसके खिलाफ छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 36 और 59(क) के तहत गैर-जमानती मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। डोंगरगढ़ क्षेत्र में इससे पहले भी अवैध शराब से जुड़े कई बड़े मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें टैंकर, रैपर और पैकिंग सामग्री तक जब्त की गई थी।

प्राचीन इतिहास और विरासत का डिजिटाइजेशन, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का प्रमाण

कोरबा। देश की बिखरी हुई समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को सहेजने के लिए भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा ज्ञानभारतम पांडुलिपि सर्वेक्षण अभियान की शुरुआत की गई है। कोरबा जिले के तीन प्रमुख स्थलों का सफलतापूर्वक सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है। इस दौरान कुल 575 पांडुलिपियों को ज्ञानभारतम ऐप पर अपलोड किया जा चुका है।यह जिले के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बन गई है। इस महत्वपूर्ण अभियान के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जिला स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। इस अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी-कर्मचारियों सहित वालंटियर्स को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। सभी को मोमेंटो, प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा, जिससे अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी। यह अभियान केंद्र सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के निगरानी में है। जिसके लिए अपर कलेक्टर ओंकार यादव को नोडल अधिकारी



बनाया गया है। कोरबा जिले के फुलवारी गांव में डॉ रविंद्र नाथ मिश्र के निवास स्थान पर एक प्राचीन पांडुलिपि मिली है। पुरातत्व के जानकार इसे छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन पांडुलिपियों में से एक बता रहे हैं। इस पांडुलिपि में डॉ रविंद्र मिश्र के परिवार का उल्लेख है। गांव के साथ ही एक नाटक का भी उल्लेख किया गया है। प्रशासन की पूरी टीम उनके घर पहुंची और पांडुलिपियों का सर्वेक्षण किया है। डिजिटलाइजेशन के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस अभियान के तहत लोगों को एक भ्रम भी है कि पांडुलिपियों को उनसे लेकर संग्रहालय या कहीं रखा जाएगा, लेकिन कलेक्टर ने यह स्पष्ट किया है की पांडुलिपि जिनके पास है, उनके पास ही रहेंगी। मालिकाना हक का हस्तांतरण नहीं होगा। केवल इसका संरक्षण कर उनकी स्कैनिंग होगी और एक डिजिटल स्टोरेज बनेगा। ज्ञान भारतम के मैप पर जीपीएस मैप पर इन पांडुलिपियों को दर्शाया जाएगा ताकि इनकी लोकेशन सभी के साथ साझा की जा सके और ऐतिहासिक महत्व की कौन सी पांडुलिपि कहां है, इसका एक डिजिटल स्टोरेज उपलब्ध हो, जिसकी जानकारी जनमानस के पास भी उपलब्ध रहेगी। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने बताया कि जो ऐतिहासिक पांडुलिपियां हैं, जो विरासत है, फिर चाहे वह धातु की हो, तांबे की हो, कागज में लिखे पुराने ऐतिहासिक धरोहर या ताड़पत्र पर हो, इन सबका संरक्षण व संवर्धन करने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा किया जा रहा है। इसमें अभी तक हमको 17 अलग-अलग लोकेशन पर प्राइवेट और निजी व्यक्ति या जिला संग्रहालय है, जो जमींदार हैं, वहां से ऐतिहासिक पांडुलिपि मिली है। उन सभी का सर्वे कर उनके डिजिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है।कलेक्टर ने बताया कि ज्ञानभारतम पांडुलिपि अभियान के तहत देश के सभी पांडुलिपि का संरक्षण होगा। एक रिपोजिटरी बनेगी ताकि जो देश का ज्ञान है, वह सबके साथ में सांझा हो सके। आपके माध्यम से मैं सभी से अनुरोध भी करना चाहूंगा कि यदि आपके पास में कोई पुराने पांडुलिपि है, रिकॉर्ड्स है। उनकी जानकारी हमारे नोडल अधिकारी को प्रदान करें ताकि इसका डिजिटाइजेशन किया जा सके। इसमें किसी भी तरह का ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। जिस व्यक्ति के पास पांडुलिपि है, वही उसके मालिक बने रहेंगे, इसे सिर्फ संरक्षण के दृष्टिकोण से डिजिटाइजेशन किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

रामलला दर्शन योजना दुर्ग से 178 श्रद्धालु अयोध्या रवाना

दुर्ग। छत्तीसगढ़ शासन की रामलला दर्शन योजना के अंतर्गत दुर्ग जिले में भक्ति और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला। दुर्ग रेलवे स्टेशन से 178 श्रद्धालुओं का बड़ा जत्था आस्था स्पेशल ट्रेन के माध्यम से राम की जन्मभूमि अयोध्या के लिए रवाना हुआ। इस अवसर पर पूरा स्टेशन परिसर जय श्री राम के जयघोष से गुंजायमान रहा, जिससे वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो गया। दुर्ग नगर पालिक निगम की महापौर अलका बाघमार ने इस विशेष ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने स्वयं स्टेशन पहुंचकर यात्रियों का पुष्पमालाओं से आत्मीय स्वागत किया। मेयर अलका ने यात्रियों की सुखद व सुरक्षित यात्रा की मंगलकामना की। महापौर ने योजना की सराहना करते हुए कहा कि यह पहल आम नागरिकों के वर्षों पुराने सपने को साकार कर रही है। आपको बता दें कि श्रद्धालुओं को केवल अयोध्या ही नहीं, बल्कि काशी विश्वनाथ के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त होगा, इस जत्थे की रवानगी के साथ ही योजना का लाभ लेने वाले कुल श्रद्धालुओं की संख्या 45,900 से बढ़कर 46,750 पहुंच जाएगी।

जिले में 01 मई होगा समाधान शिविर का आयोजन

महासमुंद। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप आमजन को सुगम, पारदर्शी एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत 01 मई से 05 जून तक जिले में कुल 41 समाधान शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें महासमुंद विकासखंड में 10, बागबाहरा में 7, पिथौरा में 9, बसना में 7, सरायपाली में 7 तथा तुमगांव नगरीय निकाय में एक क्लस्टर शामिल है। शिविरों में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां शासन की योजनाओं की जानकारी दी जाएगी तथा पात्र हितग्राहियों को जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में लाभ वितरण भी किया जाएगा। समाधान शिविर का आयोजन 01 मई 2026 को महासमुंद विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बम्हनी के हाई स्कूल मैदान में आयोजित होगा, जिसमें 16 ग्राम के नागरिकों का मांग एवं शिकायत संबंधी आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। बागबाहरा विकासखण्ड अंतर्गत ग्राम पंचायत खुटेरी के प्राथमिक शाला खुटेरी में आयोजित समाधान शिविर में 17 ग्रामों के नागरिक शामिल होंगे।

कॉलेज में अटेंडेंस एडजस्टमेंट के नाम पर छात्रों से अवैध वसूली

जगदलपुर। धरमपुरा स्थित वेदमाता गायत्री शिक्षा महाविद्यालय में बीएड-डीएड के छात्रों से उपस्थिति (अटेंडेंस) लगाने के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। कॉलेज प्रबंधन द्वारा परीक्षा में शामिल होने के लिए छात्रों से उपस्थिति के नाम पर मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार महाविद्यालय के प्रोफेसर्स, प्रोफेसर कामना वर्मा ऐसे छात्रों को कॉल कर बुला रही है, जिनकी अटेंडेंस कम है और उसके बाद उपस्थिति लगाने के लिए उनसे पैसे की डिमांड की जा रही है। पड़ताल में पता चला कि किसी छात्र से 15 हजार तो किसी से 20 से 25 हजार रुपए सेमेस्टर के हिसाब से डिमांड की जा रही है और पैसे नहीं देने पर परीक्षा में बैठने नहीं देने की बात कही जा रही है। खास बात यह है कि छात्रों द्वारा इसकी रसीद मांगने पर कोई रसीद नहीं दी जा रही है। खुलेआम इन जिम्मेदारों द्वारा छात्रों से अवैध वसूली की जा रही है। खुद उसने 35 हजार रुपए दिया, क्योंकि एग्जाम में बैठने के लिए 75 से 80त्न अटेंडेंस अनिवार्य है। ऐसे में जिन छात्रों की अटेंडेंस कम है।

प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु प्राक्चयन परीक्षा 10 मई को

जीपीएम। मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा प्रयास आवासीय विद्यालय योजना के तहत राज्य में संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए प्राक्चयन परीक्षा आगामी 10 मई सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगा। प्रवेश परीक्षा के लिए जीपीएम जिले में 4 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। जिले में परीक्षार्थियों की कुल संख्या 671 है। कलेक्टर श्रीमती लीना कमलेश मंडावी ने आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के निर्देशानुसार सुचारू रुप से परीक्षा संचालन हेतु श्री दिलेराम डाहिरे संयुक्त कलेक्टर को जिला नोडल अधिकारी और संबंधित परीक्षा केन्द्रों के प्राचार्य को केन्द्राध्यक्ष के साथ ही प्रेक्षक नियुक्त किए गए हैं। परीक्षा केन्द्र मिश्री देवी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गौरेला के लिए केन्द्राध्यक्षण विद्यालय के प्राचार्य को तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत गौरेला को श्री ज्ञानदर राम भगत प्रेक्षक नियुक्त किया गया है।

जिले के प्रभारी सचिव ने पीएम श्रीस्कूल मानपुर का किया निरीक्षण

मोहला। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ जिले के प्रभारी सचिव पीएस एल्मा ने अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान मानपुर स्थित पीएमश्री स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्कूल पहुंचने पर विद्यार्थियों ने अंग्रेजी में स्वागत गीत प्रस्तुत कर प्रभारी सचिव पीएस एल्मा का स्वागत किया। प्रभारी सचिव पीएस एल्मा ने विद्यालय के शिक्षकों से परिचय प्राप्त करते हुए स्कूल की शैक्षणिक एवं मूलभूत व्यवस्थाओं का विस्तार से जायजा लिया। उन्होंने विद्यार्थियों की उपस्थिति, कुल दर्ज संख्याए शिक्षकों की उपलब्धता तथा विद्यालय में पेयजल, रनिंग वाटर, साफ-सफाई और विद्युत व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। प्रभारी सचिव ने सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुचारु रखने एवं कमियों को शीघ्र दूर करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाओं पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने विद्यार्थियों के हेल्थ कार्ड बनाने के निर्देश दिए, ताकि नियमित मासिक स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जा सके।

बंदूक छोड़ स्टार्टअप की राह पर युवा, बस्तर यूनिवर्सिटी में इनोवेशन महाकुंभ का आयोजन

बस्तर। छत्तीसगढ़ का बस्तर जो कभी नक्सलवाद की वजह से सुर्खियों में रहता था, अब एक नई पहचान गढ़ने की ओर बढ़ रहा है। शिक्षा, नवाचार और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। युवा अब बंदूक नहीं, बल्कि बिजनेस और स्टार्टअप की भाषा सीखने को तैयार हैं। इसी कड़ी में बस्तर यूनिवर्सिटी में इनोवेशन महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है।

यह आयोजन 4 और 5 मई को होगा, जो बस्तर के भविष्य की नई इबारत लिख सकता है। इस महाकुंभ में 1 हजार से अधिक पढ़े-लिखे बेरोजगार आदिवासी छात्र शामिल होंगे। इन युवाओं को रोजगार, स्टार्टअप और व्यवसाय की बारीकियां सिखाई जाएंगी। कार्यक्रम में 642 छात्राएं और 389 छात्र हिस्सा लेंगे। ये सभी प्रतिभागी बस्तर संभाग के अलग-अलग



जिलों से आएंगे। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा और बीजापुर के युवा इसमें शामिल रहेंगे। यह मंच उन्हें नौकरी ढूंढने से आगे बढ़कर खुद रोजगार देने वाला बनाने की दिशा देगा। इस कार्यक्रम की सबसे खास बात यह है कि इसमें करीब 200 पुनर्वासित माओवादी भी शामिल होंगे। जो कभी बंदूक के रास्ते पर थे, अब वे विकास और रोजगार की राह चुन रहे हैं। उन्हें उद्योग, स्टार्टअप और आत्मनिर्भरता की शिक्षा दी जाएगी।

यह पहल नक्सलवाद के खत्म होने और समाज में सकारात्मक बदलाव का मजबूत संकेत है। बस्तर अब हिंसा नहीं, बल्कि विकास की कहानी लिखने की ओर बढ़ रहा है। इस महाकुंभ में पूरे देश से 50 से अधिक विशेषज्ञ शामिल होंगे।

मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, आईआईटी भिलाई, ष्टत्रष्टह्लस्ङ्क, और अन्य संस्थानों के विशेषज्ञ युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे। कॉमर्स, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े विभाग भी इसमें भाग लेंगे। स्वावलंबी भारत अभियान के सदस्य भी युवाओं को आत्मनिर्भर बनने के गुर सिखाएंगे। यह आयोजन बस्तर को राष्ट्रीय स्तर से जोड़ने का काम करेगा।

कार्यक्रम की सभी सत्रों का अनुवाद बस्तर की स्थानीय हल्बी भाषा में भी किया जाएगा। ताकि हर वर्ग का युवा इसे आसानी से समझ सके और उससे लाभ उठा सके। करीब 7 हजार से अधिक छात्र इस कार्यक्रम को ऑनलाइन माध्यम से भी देखेंगे। यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए यह ज्ञान दूर-दराज के गांवों तक पहुंचेगा। यह पहल शिक्षा को स्थानीय स्तर पर सुलभ बनाने का मजबूत उदाहरण है। कार्यक्रम का शुभारंभ छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और गृह मंत्री करेंगे। जबकि समापन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे।

इससे कार्यक्रम की गंभीरता और महत्व और भी बढ़ जाता है। सरकार का सीधा फोकस अब बस्तर के युवाओं को आगे बढ़ाने पर है। कुलपति मनोज श्रीवास्तव के मुताबिक यह सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि एक आंदोलन है। जो बस्तर के युवाओं को नई दिशा देने का काम करेगा। नक्सलवाद की छाया से निकलकर अब बस्तर विकास और नवाचार की राह पर बढ़ रहा है। इनोवेशन महाकुंभ इस बदलाव का प्रतीक बन सकता है।

आवेदनों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करें: पीएस एल्मा

मोहला। जिले के प्रभारी सचिव पीएस एल्मा ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय योजनाओं के प्रगति समीक्षा की। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस यशपाल सिंह, डीएफओ दिनेश पटेल उपस्थित रहे। प्रभारी सचिव श्री एल्मा ने सुशासन तिहार 2026 की तैयारियों के संबंध में विस्तृत जानकारी लेते हुए सभी विभागों की कार्य योजनाओं की समीक्षा की।

उन्होंने निर्देश दिए कि सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त सभी आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जाए तथा सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन गंभीरता से करें। विशेष रूप मुख्यमंत्री



जनदर्शन के तहत प्राप्त आवेदनों के शीघ्र एवं प्राथमिकता के आधार पर निराकरण के निर्देश दिए गए। उन्होंने शिविर स्थलों पर पेयजलए बैठक व्यवस्था एवं शिविर आयोजन के लिए स्थान चिन्हांकन सहित आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही वर्तमान में संचालित जनगणना कार्यों की तैयारियों की भी समीक्षा की। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए शिशु मृत्यु दर एवं कुपोषण की स्थिति के संबंध में स्वास्थ्य तथा महिला एवं बाल विकास विभाग को समन्वित रूप से कार्य करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने महिलाओं के स्वास्थ्य, सुपोषण तथा मातृ-शिशु मृत्यु दर में सुधार हेतु संयुक्त प्रयासों पर बल दिया। हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं का नियमित फॉलोअप, संस्थागत प्रसव एवं टीकाकरण बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा के दौरान जिले में स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजनाओं की प्रगति का विकासखण्डवार आकलन किया गया। उन्होंने कहा कि जिले में पीएम आवास की प्रगति संतोषजनक है, लेकिन जिन विकासखण्डों में प्रगति कम है।

संक्षिप्त समाचार

अंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट में ज्ञानेश्वरी को गोल्ड मेडल

रायपुर। अंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट



आईबीएफसी यूनिवर्सल कप-2026 में ज्ञानेश्वरी यादव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 53 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। समोआ के एपिया स्थित तुआनाईमाटो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 25 अप्रैल से 2 मई तक अंतरराष्ट्रीय वेटलिफ्टिंग टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में 70 देशों के लगभग 500 खिलाड़ी एवं 200 अधिकारी शामिल हो रहे है। ज्ञानेश्वरी ने शानदार प्रदर्शन के साथ अपने ग्रुप में प्रथम स्थान हासिल कर गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। यह कॉमनवेल्थ गेम्स-2026 के लिए क्वालीफिकेशन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। ज्ञानेश्वरी इससे पहले जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल और सीनियर कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीत चुकी है। गौरवशाली और प्रदेश का नाम रोशन करने वाली उपलब्धियों के लिए राज्य शासन द्वारा उन्हें गुण्डाधुर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ज्ञानेश्वरी अभी छत्तीसगढ़ पुलिस में राजनांदगांव में कार्यरत है। अपने कोच श्री अजय लोहार विश्वकर्मा के प्रशिक्षण और मार्गदर्शन से ज्ञानेश्वरी इस मुकाम तक पहुंची है।

रिजल्ट से असंतुष्ट 10वीं-12वीं के छात्र 14 मई तक कर सकेंगे आवेदन

रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2026 के परिणाम जारी होने के बाद छात्रों के लिए अहम निर्देश जारी किए हैं। जो विद्यार्थी अपने प्राप्त अंकों से संतुष्ट नहीं हैं वे पुनर्गणना, पुनर्मूल्यांकन और उत्तर पुस्तिका की छाया प्रति के अवलोकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। मंडल द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, छात्र 14 मई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। गौरतलब है कि हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा का परिणाम 29 अप्रैल 2026 को घोषित किया गया। मंडल ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा परिणाम जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर ही आवेदन करना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे निर्धारित समय सीमा के भीतर आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी करें, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके।

हादसे में मृतक परिवार को मिली बड़ी राहत, 2 लाख रुपए की सहायता स्वीकृत

रायपुर। प्रदेश सरकार की जनहितकारी पहल का असर अब जमीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत जशपुर जिले के एक पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है, जिससे कठिन समय में उन्हें महत्वपूर्ण सहारा मिला है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जशपुर जिले के फरसाबहार तहसील अंतर्गत ग्राम फरदबहार निवासी स्वर्गीय विनोद साय की नदी में नहाने के दौरान पैर फिसल जाने से गंभीर चोट लग गई थी। परिजनों ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इस दुखद घटना के बाद परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहा था। मृतक की पत्नी चिरंजीवी पैंकरा ने अपनी समस्या को लेकर बगिया स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किया और तेंदूपत्ता सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत सहायता की मांग की। प्रारंभिक स्तर पर उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा था। मामले की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय ने त्वरित संज्ञान लेते हुए संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश दिए। प्रशासनिक पहल से प्रक्रिया में तेजी लाई गई और अंततः परिजनों को 2 लाख रुपए की बीमा सहायता राशि स्वीकृत कर दी गई। सहायता राशि प्राप्त होने पर परिजनों ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार ने उनके दुख की घड़ी में संवेदनशीलता के साथ मदद पहुंचाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय की सक्रिय कार्यप्रणाली की भी सराहना की।

लखनऊ से रायपुर आ रही फ्लाइट के सामने आ गया बंदर

रायपुर। लखनऊ से रायपुर आ रही एक फ्लाइट में उस समय बड़ा हादसा टल गया, जब लैंडिंग के दौरान अचानक रनवे पर एक बंदर आ गया। स्थिति को भांपते हुए पायलट ने तुरंत इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, जिससे विमान समय रहते रुक गया और संभावित दुर्घटना टल गई। बताया जा रहा है कि फ्लाइट में कुल 132 यात्री सवार थे, जिनमें आधे से ज्यादा यात्री रायपुर के रहने वाले थे। घटना के दौरान कुछ समय के लिए विमान में अफरा-तफरी का माहौल बन गया, लेकिन पायलट की सूझबूझ से सभी यात्री सुरक्षित रहे।एयरपोर्ट प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रनवे को खाली कराया और स्थिति को नियंत्रण में लिया। इसके बाद विमान को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाया गया। फिलहाल सभी यात्री सुरक्षित हैं और किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने घटना की जांच शुरू कर दी है और रनवे पर जानवरों की आवाजाही रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी करने की बात कही है।

नारी शक्ति वंदन के संकल्प को मिला महिलाओं का व्यापक समर्थन

राज्यसभा सांसद वर्मा के नेतृत्व में महिला प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट कर जताया आभार

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज विधानसभा स्थित कार्यालय में राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा के नेतृत्व में महिला प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर महिला प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में विधानसभा में आयोजित विशेष सत्र तथा इस संबंध में पारित शासकीय संकल्प के लिए विशेष धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक पहल महिलाओं के सम्मान, सशक्तिकरण और उनके अधिकारों की दिशा में एक मजबूत कदम है, जिससे समाज में सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होगा।

महिला प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में प्रदेश में महिलाओं के उत्थान हेतु किए जा रहे प्रयासों



की सराहना करते हुए विश्वास व्यक्त किया कि राज्य में महिला सशक्तिकरण को और अधिक गति मिलेगी तथा महिलाओं की भागीदारी सभी क्षेत्रों में सुदृढ़ होगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन जैसी ऐतिहासिक पहल समाज में समानता और न्याय के नए आयाम स्थापित करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश की महिलाएं विकास यात्रा की सशक्त सहभागी हैं और उनके सशक्तिकरण के बिना समग्र विकास की परिकल्पना अधूरी है।मुख्यमंत्री ने महिला प्रतिनिधियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

सदन का ऐतिहासिक सत्र सुनने विधानसभा पहुंची मिस इंडिया छत्तीसगढ़ ने मुख्यमंत्री से की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज विधानसभा में मिस इंडिया छत्तीसगढ़ 2026 सुश्री अनुष्का सोन ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर सुश्री अनुष्का ने मुख्यमंत्री को नारी सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों के लिए धन्यवाद देते हुए कहा कि महिलाओं के सम्मान और अधिकारों को लेकर विशेष सत्र आयोजित करना एक प्रेरणादायक पहल है। उन्होंने कहा कि इससे समाज में सकारात्मक संदेश जाता है और महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की प्रेरणा मिलती है।

सुश्री अनुष्का ने बताया कि वे आज विधानसभा की ऐतिहासिक कार्यवाही को सुनने विशेष रूप से पहुंची थीं और इस अनुभव को उन्होंने अत्यंत प्रेरणादायक बताया। उन्होंने कहा कि नीति निर्माण की प्रक्रिया को करीब से देखना उनके लिए एक नई सीख रही, जिससे वे समाज में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए और अधिक प्रोत्साहित कर सकेंगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर



पर कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सुखद है कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों से महिलाएं आगे आकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं, जो एक सशक्त और जागरूक समाज की पहचान है। मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास जताया कि इस तरह की पहल महिलाओं के आत्मविश्वास को और मजबूत करेंगी तथा उन्हें नेतृत्व की भूमिका में आगे आने के लिए प्रेरित करेंगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि नई पीढ़ी की बेटियां शिक्षा, कला, खेल और सामाजिक क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं, जो प्रदेश के लिए गर्व का विषय है। उन्होंने सुश्री अनुष्का सोन को उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे समाज में सकारात्मक बदलाव की प्रेरक बनें।

छत्तीसगढ़ में ईडी का छापा, ऑफिस-घर में दबिश

दुर्ग और बिलासपुर में बिल्डर कारोबारी के ठिकानों पर रेड

रायपुर। छत्तीसगढ़ के दुर्ग और बिलासपुर शहर में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापेमारी की है। दुर्ग शहर में अमर इंफ्रा के डायेरक्टर और बीजेपी नेता चतुर्भुज राठी के महेश कालोनी स्थित निवास और ऑफिस पर रेड मारी है। टीम वहां पर कंपनी के दस्तावेज और कागजात खंगाल रही है। ईडी भिलाई-3 के विश्वदीप कॉलोनी निवासी गोविंद मंडल के घर और फैक्ट्री में भी दबिश देकर जांच कर रही है। इसके साथ ही बिलासपुर में सर्राफा कारोबारी विवेक अग्रवाल के घर और सदर बाजार के श्रीराम ज्वेलर्स पर भी ईडी ने दबिश दी है।

बताया जाता है कि यह कार्रवाई शराब घोटाले के फरार आरोपी विकास अग्रवाल के सिंडिकेट से जुड़े तार खंगालने के लिए हो रही है। क्योंकि वह शराब कारोबारी अनवर ढेबर का करीबी है। इसके साथ ही विवेक अग्रवाल का भाई भी बताया जाता है। चर्चा यह भी है कि यह मामला भारतमाला परियोजना से भी जुड़ा है।

बता दें कि बीजेपी नेता चतुर्भुज राठी अमर इंफ्रा के संचालक हैं। हाल ही में उनके कोयला कारोबार में भी उतरने की बात कही जा रही है।



चतुर्भुज राठी ने साल 1986 में अमर बिल्डर्स को एकल स्वामित्व के रूप में कंपनी की नींव रखी। अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार किया और देशभर में बड़ी परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं।

वहीं ईडी की टीम ने बिलासपुर में भी दबिश देकर शहर के बड़े सराफा कारोबारी विवेक अग्रवाल के घर और दुकान पर सुबह से कागजातों की छानबीन कर रही है। उनकी मध्यनगरी चौक में श्रीराम ज्वेलर्स के नाम से ज्वेलरी शॉप है।

दो हजार करोड़ के कथित घोटाले के सिंडिकेट का मेंबर विकास अग्रवाल फिलहाल फरार है, जिसकी पतासाजी में पुलिस और ईडी की टीम जुटी है।

मुख्यमंत्री साय के नेतृत्व में विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने सुलझाए लंबित प्रकरण

रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन की जनकल्याणकारी नीतियों एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में संचालित योजनाओं का सकारात्मक प्रभाव अब प्रदेशभर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की सक्रियता के चलते राज्य के विभिन्न जिलों में वर्षों से लंबित विद्युत प्रकरणों का त्वरित निराकरण किया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल रही है।

मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण एवं मध्यमवर्गीय परिवारों को बड़ी राहत प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत लंबित विद्युत देयकों की समीक्षा कर उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत से अधिक तक की छूट दी जा रही है। इसी क्रम में सूरजपुर जिले के एक उपभोक्ता को 90 हजार रुपये से अधिक के बकाया बिल पर 55 हजार



रुपये से अधिक की छूट प्रदान की गई, जिससे उन्होंने शेष राशि का भुगतान कर अपना खाता पूर्णतः शून्य कर लिया।

फोरम की सक्रिय पहल के तहत लंबे समय से लंबित अमानत राशि (सिक्योरिटी डिपॉजिट) के मामलों का भी निराकरण किया जा रहा है। एक प्रकरण में एक वर्ष से लंबित राशि को उपभोक्ता के बैंक खाते में सीधे हस्तांतरित किया गया। साथ ही, इस प्रकार की देरी पर फोरम द्वारा संबंधित अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी गई है कि भविष्य में समय-सीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए।

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं से जुड़े सभी प्रकरणों का समयबद्ध एवं पारदर्शी तरीके से निराकरण किया जाए, ताकि आम नागरिकों को अनावश्यक मानसिक एवं आर्थिक परेशानियों का सामना न करना पड़े।

विभागीय अधिकारियों ने प्रदेश के सभी बकायादार उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना 2026 का अधिकतम लाभ उठाएं। शासन का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक परिवारों को पुराने बकाया से मुक्ति दिलाकर उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाया जा सके।

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 मई को

रायपुर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) नई दिल्ली के निर्देशानुसार वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले नेशनल लोक अदालत के अनुक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, बिलासपुर के निर्देशानुसार शनिवार 09 मई 2026 को छत्तीसगढ़ राज्य में तालुका न्यायालय के स्तर से लेकर उच्च न्यायालय स्तर तक सभी न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजित कर राजीनामा योग्य प्रकरणों में पक्षकारों की आपसी सुलह समझौता से निराकृत किये जाएंगे। नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों के निराकरण के लिए इस स्थापना अन्तर्गत विभिन्न थानाओं में पदस्थ पैरालीगल वालिन्टियर्स द्वारा अपने क्षेत्रों में विभिन्न सुदुर अंचलों के गांवों, नगरों, कस्बों में नेशनल लोक अदालत के लाभों के बारे में बताते हुए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। इसी प्रकार विभिन्न विभागों के नगरों, गांवो में भ्रमण करने वालों वाहनों के माध्यम से भी उक्त नेशनल लोक अदालत का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

नेशनल लोक अदालत में राजीनामा के आधार पर निराकरण हेतु दाण्डिक राजीनामा योग्य प्रकरण, चेक



बाउन्स अर्थात् 138 वाले मामले, बैंक रिकवरी अर्थात् प्री-लिटिगेशन प्रकरण, मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरण, भरण-पोषण धारा 125 के प्रकरण, परिवार न्यायालय से संबंधित प्रकरण, श्रमिक प्रकरण, जमीन विवाद प्रकरण, विघुत प्रकरण, जलकर प्रकरण, सम्पत्ति कर, टेलीफोन प्रकरण तथा राजस्व प्रकरणों को नियत किया गया है और उपस्थित पक्षकारगण के मध्य उपजे विवाद को वैकल्पिक समाधान के तहत लोक अदालत में उनके मध्य राजीनामा की सम्भावनाओं को तलाश करते हुए, उक्त नेशनल लोक अदालत के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिक से अधिक प्रकरणों का चिन्हांकित करते हुए रखा जाना है। नेशनल लोक अदालत के संबंध में अधिक जानकारी के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कबीरधाम के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है तथा नम्बर 07741-299950 पर भी जानकारी ली जा सकती है। नेशनल लोक अदालत की तैयारियों के संबंध में अधिवक्तागण, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, नगर पालिका, बीएसएनएल, विद्युत विभाग तथा समस्त बैंको से भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है।

रायपुर रेल मंडल के टिकट चेकिंग स्क्वाड ने डुप्लीकेट एमएसटी रेल टिकट बनाने वालों को पकड़ा

रायपुर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के वाणिज्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की सक्रियता से निर्देशानुसार ट्रेन संख्या 68705 (रायपुर-डोंगरगढ़ लोकल) में विशेष टिकट जांच अभियान चलाया गया। दुर्ग में आयोजित फोर्ट्रेस चेकिंग (किलाबंदी टिकट चेकिंग) के दौरान श्रीमती प्रिया, वरिष्ठ टिकट एग्जामिनर, दुर्ग के द्वारा डुप्लीकेट एमएसटी (छः माही) का मामला पकड़ा गया, जिसकी सूचना तत्पश्चात उच्च अधिकारियों को दी गई।

टिकट चेकिंग स्टाफ ने यू टी एस ऑन मोबाइल ऐप के एमएसटी टिकट की इमेज का दुरुपयोग करते हुए डुप्लीकेट एमएसटी बनाकर यात्रा करने वाले संदिग्धों को पकड़ा।



किलाबंदी टिकट चेकिंग के दौरान एक यात्री के पास डुप्लीकेट एमएसटी टिकट पाया गया जिसकी गहनता से जांच करने पर वह टिकट डुप्लीकेट निकला पूछताछ के दौरान तथ्यों से प्लानिंग करके पकड़ा गया उसके अन्य साथी भी पकड़े गए। जांच के दौरान शंकराचार्य कॉलेज के 4 छात्र इस धोखाधड़ी में संलिप्त पाए गए। मुख्य आरोपी कुलदीप ने स्वीकार किया कि उसने फर्जी टिकट तैयार किया, जिसे उसने अपने 02 साथियों के साथ साझा किया, जिन्होंने आगे इसे अन्य लोगों तक प्रसारित किया। छात्रों के अनुसार, हर्ष नामक एक छात्र इन फर्जी टिकटों को अन्य यात्रियों को बेचने में संलिप्त था। हालांकि हर्ष अभी पकड़ नहीं आया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अवधेश कुमार त्रिवेदी ने अधीनस्थ अधिकारियों कर्मचारियों को टिकट चेकिंग के दौरान टिकटो की गहन जाँच के निर्देश दिए ।

ये पकड़े गए- (1) कुलदीप बिश्नोई उम्र 20 साल (2) यू ओंकार उम्र 20 साल (3) अखिलेश साहू उम्र 19 साल (4) राहुल साहू उम्र 20 साल।

राजधानी के बड़े निजी स्कूलों को टक्कर दिया, प्रदेश का प्रयास विद्यालय

10वीं की छात्रा कु. दीपांशी ने 98.83 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया

■ मुख्यमंत्री साय और मंत्री रामविचार नेताम ने दी बधाई

रायपुर। छत्तीसगढ़ के आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग द्वारा संचालित 'प्रयास' आवासीय विद्यालयों ने इस वर्ष छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में अभूतपूर्व सफलता हासिल कर न केवल प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक मिसाल कायम की है। विभाग के निरंतर सहयोग एवं मार्गदर्शन में सीमित संसाधनों और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद इन विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्कृष्ट परिणाम देते हुए बड़े निजी स्कूलों को कड़ी टक्कर दी है। प्रयास विद्यालयों के 13 बच्चों ने सीजी बोर्ड परीक्षा के टॉप-10 में जगह बनाने में सफलता हासिल की है।



उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कुल 17 प्रयास विद्यालय संचालित है। जिसमें नक्सल प्रभावित बच्चों से लेकर सभी वर्गों के बच्चें अध्ययनरत है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह सफलता प्रयास आवासीय विद्यालयों की अवधारणा की सार्थकता को प्रमाणित करती है। आदिम जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु किए गए सतत प्रयास की सराहना की हैं। प्रयास आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों की यह उपलब्धि राज्य के लिए गौरव का विषय है तथा यह अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत सिद्ध होगी।

प्रमुख सचिव श्री बोरा ने जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय को बताया कि प्रदेश के 50 मेरिट छात्रों में से 13 विद्यार्थी प्रयास विद्यालय के है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस बात के लिए प्रसन्नता जाहिर करते हुए भविष्य में और बेहतर कार्य करने को कहा।

श्री बोरा ने बताया कि हायर सेकेंडरी परीक्षा (कक्षा 12वीं) में प्रयास आवासीय विद्यालय के कुल 128 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। रायपुर स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय, गुडियारी की 19 छात्राओं ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए। कोरबा जिले की छात्रा कु. रागिनी कंवर ने 95 प्रतिशत अंक अर्जित कर विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया। जीव विज्ञान विषय में दो छात्राओं द्वारा 100 में 100 अंक अर्जित किया जाना विशेष उपलब्धि है। हाईस्कूल परीक्षा (कक्षा 10वीं) में भी विद्यार्थियों का प्रदर्शन अत्यंत सराहनीय रहा। कुल 119 छात्राओं में से 48 छात्राओं ने 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त किए। गणित विषय में 6 विद्यार्थियों ने शत-प्रतिशत अंक अर्जित किए। कु. दीपांशी ने 98.83 प्रतिशत अंक प्राप्त कर प्रदेश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। अनुसूचित जाति वर्ग के प्रयास आवासीय विद्यालय के विद्यार्थियों ने भी टॉप 10 मेरिट सूची में 97.5 प्रतिशत अंकों के साथ स्थान अर्जित किया। उल्लेखनीय है कि हाईस्कूल परीक्षा की प्रावीण्य सूची में कुल 42 विद्यार्थियों में से 21 विद्यार्थी आदिम जाति विकास विभाग द्वारा संचालित एकलव्य एवं प्रयास आवासीय विद्यालयों के हैं।

कार्यालय कलेक्टर (आबकारी) जिला - बालोद (छ.ग.)

//निविदा सूचना//

क्रमांक/आब./निविदा/2026/1015 बालोद, दिनांक 28/04/2026

सर्वसाधारण की विशेष जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि शासन के निर्देशानुसार बालोद नगर पालिका परिषद क्षेत्र में देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान/भवन उपयुक्त स्थल पर किराये पर लिये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की जाती है। इच्छुक निविदाकार, निविदा शर्तों के अधीन तकनीकी निविदा एवं वित्तीय निविदा के बंद लिफाफे, एक बड़े लिफाफे में रख कर बंद लिफाफा दिनांक 14.05.2026 को दोपहर 02.00 बजे तक कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी सह जिला प्रबंधक सी.एस.एम.सी.एल. जिला-बालोद में जमा कर सकेगें। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जावेगा। तकनीकी निविदा उसी दिन सायं 04.00 बजे निविदा मूल्यांकन हेतु गठित समिति के समक्ष खोला जावेगा।

निविदा के नियम/शर्तों की जानकारी एवं निविदा प्रपत्र, जिला प्रबंधक सी.एस.एम.सी.एल. जिला-बालोद के पक्ष में देय राशि रु 1180/- (अक्षरी एक हजार एक सौ अस्सी रू.) (जी.एस.टी. सहित) का बैंक ड्राफ्ट (किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी) जमा कर कार्यालयीन कार्यदिवस में कार्यालयीन समय में कार्यालय जिला प्रबंधक सी.एस.एम.सी.एल. जिला-बालोद से प्राप्त किया जा सकता है।

(कलेक्टर महोदया द्वारा अनुमोदित)

जिला आबकारी अधिकारी
हेतु कलेक्टर
जिला-बालोद (छ.ग.)

जी-262700444/5

4 मई के बाद बदल जाएगी देश की राजनीति

संतोष कुमार पाठक

देश के चार राज्यों- असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल एवं एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम एग्जिट पोल भी सामने आ चुके है। इस बार का विधानसभा चुनाव , इस मायने में बहुत खास है कि इसमें देश के दो प्रमुख राष्ट्रीय राजनीतिक दलों-कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही तृणमूल कांग्रेस, डीएमके और एआईएडीएमके जैसे ताकतवर क्षेत्रीय दलों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है। सबसे बड़ा सवाल तो लेफ्ट फ्रंट के दलों के सामने खड़ा हो गया है क्योंकि केरल की सत्ता हाथ से जाते ही उनके सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा। त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में तो लेफ्ट पार्टियां पहले ही साफ हो चुकी है। जाहिर है कि इन पांच राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश के चुनावी नतीजें सिर्फ इन राज्यों के मुख्यमंत्री ही तय नहीं करेंगे बल्कि दोनों गठबंधन- एनडीए एवं इंडिया को भी प्रभावित करेंगे। यह भी एक तथ्य है कि चाहे, चुनावी नतीजे जो भी आए लेकिन इसके बाद देश के दो प्रमुख राजनीतिक दलों में तेजी से बड़े बदलाव दिखाई देने लगेंगे। बीजेपी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर कई महीने पहले ही बदलाव की शुरुआत कर दी थी लेकिन वह बदलाव अभी संगठन के ढांचे और सरकार तक नहीं पहुंच पाया है। बताया जा रहा है कि चुनावी नतीजों के बाद नितिन नवीन की नई टीम के गठन के लिए उच्चस्तरीय बैठकों का दौर शुरू होगा। बीजेपी आलाकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस बात की है कि वो बुजुर्ग हो चुके नेताओं को संगठन से बाहर रहने के लिए कैसे मना पाते हैं क्योंकि सबसे युवा अध्यक्ष चुनने के बाद पार्टी उनकी टीम को भी युवा नेताओं से ही भरना चाहती है। पार्टी के युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में बीजेपी को पार्टी का फैसला लेने वाली सर्वोच्च ईकाई संसदीय बोर्ड, उम्मीदवारों का चयन करने वाली केंद्रीय चुनाव समिति के साथ ही राष्ट्रीय पदाधिकारियों और मोर्चों का पुनर्गठन करना है। पार्टी में नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता, मीडिया सहित विभिन्न विभागों की टीम के साथ ही राष्ट्रीय मोर्चों का भी पुनर्गठन करना है। नई टीम में एक तरफ जहां युवा और अनुभवी नेताओं का संतुलन बनाना होगा वहीं महिलाओं को भी ज्यादा से ज्यादा जगह देनी होगी। बताया जा रहा है कि 4 मई को चुनावी नतीजे आने के 10-15 दिनों के अंदर नितिन नवीन की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान हो सकता है और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय का पूरा स्वरूप ही बदला-बदला नजर आएगा। कांग्रेस में भी बड़े पैमाने पर बदलाव की शुरुआत आने वाले दिनों में होने जा रही है। मोदी-शाह की जोड़ी ने 46 वर्ष के नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर राहुल और सोनिया गांधी के सामने दुविधा की स्थिति पैदा कर दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे सुलझे हुए परिपक्व नेता तो हैं लेकिन 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को भी एक युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ युवा नेताओं की टीम तो खड़ी करनी ही पड़ेगी। इस रेस में फिलहाल सचिन पायलट सबसे आगे बताए जा रहे हैं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा, दोनों के चहेते नेता सचिन पायलट को आने वाले दिनों में कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, अगर अशोक गहलोत ने पार्टी के बुजुर्ग नेताओं के साथ मिलकर कोई और खेला नहीं कर दिया तो। कांग्रेस के अंदर वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे को लेकर भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की गुटबाजी पर लगाम कसने के लिए खड़गे को मुख्यमंत्री बनाकर बेंगलुरू भेजा जा सकता है और उनकी जगह पर दिल्ली में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को बैठाया जा सकता है।

प्रतिद्वंद्वियों की कमर तोड़कर आगे बढ़ रही है भाजपा

कमलेश पांडे

भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों की सियासी कमर तोड़कर निरंतर आगे बढ़ रही है। इससे भाजपा नीत एनडीए का कुनबा भी लगतार मजबूत हो रहा है। देश के मतदाता भी जातीय और भाषाई प्रतिद्वंद्विता से ऊपर उठकर धुर मुस्लिम तुष्टिकरण की चुनावी राजनीति की बखिया उधेड़ रहे हैं, जबकि फ्रीबिज की घोषणाओं पर अब भी मतदाता फिदा हैं। 29 अप्रैल को देश के पांच राज्यों—पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी—के विधानसभा चुनावों के जो एग्जिट पोल आए, उससे भी इसी बात के संकेत मिल रहे हैं। इससे भाजपा और उसके एनडीए साथियों की बल्ले बल्ले है।

वैसे तो अंतिम परिणाम 4 मई को ही आएंगे, लेकिन अब मीडिया की सजगता से अधिकांश एग्जिट पोल के औसत सत्य के निकट होते हैं।लिहाजा यदि एग्जिट पोल सही होते हैं तो इससे जो बड़ा राजनीतिक निष्कर्ष निकलकर सामने आया है, वह यह है कि देश की राजनीति में भाजपा के बेहतर प्रदर्शनों के बावजूद क्षेत्रीय दल अभी भी मजबूत स्थिति में हैं, क्योंकि देश पर 12 वर्षों से शासन कर रही भाजपा, बहुतेरे प्रशासनिक मामलों में कांग्रेस और समाजवादियों की राजनीतिक नकल करके और जरूरत के मुताबिक हिंदुत्व के चोलों को उतार फेंककर उन राज्यों में भी अव्वल प्रदर्शन करती दिखाई दे रही है, जहां अल्पसंख्यक मुस्लिम और ईसाई वोट अबतक निर्णायक रहते आये हैं।

ऐसा उलटफेर करके भाजपा/एनडीए कई राज्यों में अपनी पकड़ बढ़ाते दिख रहे हैं। खासकर उत्तरपूर्वी, दक्षिणी और जम्मूकश्मीर जैसे राज्यों में, जो उसकी बड़ी सफलता है। इससे आम चुनाव 2029 में भी उसे राजनीतिक फायदा मिलेगा, क्योंकि भाजपा समेत एनडीए को इससे नई सोच और नई ऊर्जा मिलेगी। जबकि इंडिया गठबंधन की आपसी रस्साकशी उन्हें 2024 की आंशिक सफलता के बाद निरंतर कमजोर करते हुए रसातल की ओर ले जा रही है। इससे कांग्रेस सुप्रीमो राहुल गांधी को राजनीतिक सबक लेनी होगी, क्योंकि वर्ष 2027 और 2028 में भी दर्जनाधिक राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।

यदि राजनीतिक बारीकीपूर्वक इन एग्जिट पोल्स से संकेतों को पढ़ा जाए तो स्पष्ट दिखाई दे रहा हैं कि उत्तर भारत, पश्चिम भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत में मजबूत सियासी पैठ बना चुकी भाजपा अब उत्तर-पूर्व समेत पूर्वी भारत में अपना विस्तार बनाए हुए है। जबकि दक्षिण भारत में भी अपने विरोधियों को राजनीतिक रूप से तोड़ने में वह सफल हो चुकी है। तमिलनाडु में डीएमके और केरल में एलडीएफ का कमजोर होकर सत्ता गंवाने की ओर बढ़ना यह सियासी चुगली कर रहा है कि जल्द ही भाजपा दक्षिण भारत में भी उसी तरह का करिश्मा करेगी, जैसा कि उसने उत्तर-पूर्व के असम और त्रिपुरा में किया है, जबकि पूर्वी भारत के पश्चिम बंगाल में करने जा रही है। इसी प्रकार तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना आदि उसकी पकड़ में जल्द आएंगे। वहीं कर्नाटक में तो वह मजबूत है ही और आंध्रप्रदेश में एनडीए की सरकार है।

यह बात दीगर है कि अपने सियासी गर्दिश के दिनों में भी कांग्रेस दक्षिण भारत, खासकर केरल में पुनर्जीवन के संकेत दे रही है। ऐसा पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के पुन: कांग्रेस के खेमे में सटने से हुआ। वहीं, क्षेत्रीय दल—डीएमके, टीएमसी आदि—अब भी अपने-अपने राज्यों में थोड़ा कमजोर होने के बावजूद निर्णायक बने हुए दिखाई दे रहे हैं। लिहाजा, 2029 लोकसभा चुनाव की दिशा में ये चुनाव राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय राजनीति की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। दक्षिण भारत में भाजपा अभी भी पूर्ण प्रभुत्व से दूर दिख रही है, जबकि बंगाल उसका सबसे बड़ा विस्तार क्षेत्र बना हुआ है। पुडुचेरी में भी एनडीए मजबूत हुआ है।



ऐसा उलटफेर करके भाजपा/एनडीए कई राज्यों में अपनी पकड़ बढ़ाते दिख रहे हैं। खासकर उत्तरपूर्वी, दक्षिणी और जम्मूकश्मीर जैसे राज्यों में, जो उसकी बड़ी सफलता है। इससे आम चुनाव 2029 में भी उसे राजनीतिक फायदा मिलेगा, क्योंकि भाजपा समेत एनडीए को इससे नई सोच और नई ऊर्जा मिलेगी।

चूंकि 2027 और 2028 में भी कई महत्वपूर्ण राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिन पर इन पांच राज्यों के चुनावी फलाफल का असर पड़ेगा। 2027 में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, उनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात जैसे अहम राज्य शामिल हैं। वहीं, 2028 में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं, उनमें कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम जैसे महत्वपूर्ण राज्य शामिल हैं। चूंकि इन चुनावों की अंतिम तिथियाँ भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना के अनुसार तय होंगी, इसलिए कार्यक्रम में बदलाव संभव है।

इसलिए मौजूदा चुनावी एग्जिट पोल के कतिपय मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं -

पहला, असम में भाजपा मजबूत हुई है, क्योंकि एग्जिट पोल भाजपा-एनडीए को लगातार तीसरी बार स्पष्ट बहुमत देते दिख रहे हैं। इससे संकेत मिलता है कि हिमंता विश्व सरमा (।द्वद्वड्डठ्ठह्लड्ड क्कह्व्ह्य2ड्ड स्ड्डह्द्वड्ड) की नेतृत्व शैली और भाजपा का पूर्वोत्तर मॉडल अभी भी प्रभावी है।

दूसरा, भाजपा की रणनीति से पुडुचेरी में भी एनडीए को फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एग्जिट पोल एनडीए की वापसी दिखा रहे हैं। यहां भाजपा ने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर अपना आधार मजबूत किया है।

तीसरा, पश्चिम बंगाल में टीएमसी और भाजपा के बीच कांटे की टक्कर के बीच भाजपा को बढ़त मिलने के स्पष्ट आसार नजर आ रहे हैं। क्योंकि अधिकांश एग्जिट पोल में भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच बेहद करीबी मुकाबला दिखाया गया है। वहीं कुछ सर्वे यानी 5 में से 4 भाजपा को सीधी बढ़त दे रहे हैं, जबकि कुछ ममता बनर्जी की वापसी बता रहे हैं। इसका मतलब है कि बंगाल में सत्ता विरोधी लहर और ध्रुवीकरण दोनों साथ-साथ काम कर रहे हैं। चूंकि विशेष गहन पुनरीक्षण (स्ड्ढक्र) के तहत लाखों वोटरों के नाम हटाने को लेकर विवाद है, जिसे भाजपा ने बोगस वोट हटाने के रुप में सही ठहराया है, जबकि टीएमसी ने इसे अपने वोटरों को हटाने की साज़िश बताया है। रुझानों के मुताबिक, महिलाओं ने ममता बनर्जी पर पुन: भरोसा जताया है,जो टीएमसी की बड़ी ताकत है।

चौथा, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति कायम, लेकिन नया मोड़ आने के आसार, क्योंकि टीवीके मजबूती से उभरी है और राज्य की सत्ता पाने के करीब पहली बार में ही पहुंच चुकी है। भले ही अधिकांश सर्वे डीएमके गठबंधन की वापसी का संकेत दे रहे हैं, लेकिन अभिनेता विजय (ड्ढद्बद्धड्ड4) की पार्टी टीवीके (ञ्जङ्क्य) को बड़ी ताकत के रूप में उभरता दिखाया गया है। इसका मतलब है कि एआईडीएमके (ढ्ढष्ठस्थ्य) का सहयोग टीवीके (ञ्जङ्क्य) को तमिल राजनीति में मिला तो एक नया राजनीतिक ध्रुव भी बन सकता है।

पांचवां, केरल में कांग्रेस गठबंधन की वापसी से इंडिया गठबंधन को कुछ राहत मिल सकती है। चूंकि लगभग सभी एग्जिट पोल कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ को बढ़त दे रहे हैं। इसलिए यह संकेत मिलता है कि वाम मोर्चे की लगातार दो कार्यकाल वाली सरकार के खिलाफ सत्ता परिवर्तन की भावना बनी है। इससे कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ को फायदा मिला, जो कांग्रेस के राजनेता शशि थरूर की बड़ी उपलब्धि है।

यदि समग्र राजनीतिक निष्कर्ष निकाला जाए तो भाजपा उत्तर-पूर्व और पूर्वी भारत में विस्तार बनाए हुए है। कांग्रेस दक्षिण भारत, खासकर केरल में पुनर्जीवन के संकेत दे रही है। क्षेत्रीय दल—डीएमके, टीएमसी आदि—अब भी अपने राज्यों में निर्णायक हैं। 2029 लोकसभा चुनाव की दिशा में ये चुनाव राष्ट्रीय बनाम क्षेत्रीय राजनीति की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। दक्षिण भारत में भाजपा अभी भी पूर्ण प्रभुत्व से दूर दिख रही है, जबकि बंगाल उसका सबसे बड़ा विस्तार क्षेत्र बना हुआ है।

पुराण दिग्दर्शन ....



सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

यही इस आख्यान का भाव है। न यहाँ इन्द्र का कुछ विश्वासघात है न गर्भपात की कोई बात है, किन्तु वैज्ञानिक रहस्य न समझ सकने वाले महाशयों की कोरी खुराफात है।

ऐतिहासिक समन्वय

इन्द्र के इस कृत्य पर यदि ऐतिहासिक दृष्टि से विचार किया जावे तब भी कुछ उचित आक्षेप हो सकने की सम्भावना नहीं, क्योंकि दिति ने एक वर्ष पर्यन्त कठिन तपश्चर्या करके देववृन्द को जड़ से उखाड़ फेंकने वाला भयङ्कर पुत्र उत्पन्न करने की अभिलाषा की थी जैसा कि श्रीमद्भागवत (6 । 18) में लिखा है-

मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ती पर्य्यचिन्तयत् ।।23।।
कदा नु भ्रातृहन्तारमिन्द्रियाराममुल्वणम्।
अक्लिन्नहृदयं पापं घातयित्वा शये सुखम् ।।24।।

अर्थात् [दिति] शोक से प्रदीप्त हुवे क्रोध में जलती हुई की तरह सोचने लगी कि वह दिन कब होगा जब कि मैं भाई का वध करने वाले पापी इन्द्र को - जो कि मुझे हलाहल विष के समान दुर्जन दीख पड़ता है- एवं इस समय फूला नहीं समाता मरवा कर आराम से सोऊंगी। यहीं क्यों? जब कश्यप जी ने प्रसन्न होकर दिति से कहा कि-वरं वरय वामोरु! तब भी वह अपने इस जघन्य उद्देश्य से न टली और कड़क कर बोली कि- पुत्रमिन्द्रहणं वृणे अर्थात्- मैं इन्द्र को मारने वाला पुत्र मांगती हूं। विज्ञ पाठक ही स्वयं सोच सकते हैं कि ऐसी दशा में आत्मरक्षा के लिये इन्द्र का क्या कर्तव्य हो सकता है? कोई भी बुद्धिमान् दिति की पूर्वोक्त विघातक-भावना की विद्यमानता में इन्द्र के इस अकार्यों की निन्दा नहीं कर सकता! वर्तमान कानून भी आत्मरक्षा के लिये किए गए किसी अपराध को उतना दण्डनीय निर्धारित नहीं करता। अत: नैतिक दृष्टि से भी यहाँ कोई आक्षेप नहीं किया जा सकता।

क्रमशः ...

विश्व मजदूर दिवस : मेहनत की नींव पर टिकी दुनिया

कातिलाल मांडोत

मानव सभ्यता के विकास की कहानी अगर ध्यान से पढ़ी जाए तो उसके हर पन्ने पर मजदूरों की मेहनत, पसीना और संघर्ष साफ दिखाई देता है। चाहे ऊंची-ऊंची इमारतें हों, विशाल पुल हों, फैक्ट्रियां हों या फिर खेतों में लहलहाती फसलें—हर जगह एक मजदूर की मेहनत छिपी होती है। फिर भी विडंबना यह है कि समाज के इस सबसे महत्वपूर्ण वर्ग को अक्सर वह सम्मान, सुरक्षा और सुविधाएं नहीं मिल पातीं, जिसके वे हकदार हैं। इसी सच्चाई को याद दिलाने और मजदूरों के अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है।

मजदूर दिवस केवल एक उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक संघर्ष की याद है। यह



उन दिनों की कहानी कहता है जब मजदूरों को 15-16 घंटे तक काम करना पड़ता था, बिना किसी निश्चित समय सीमा और बिना पर्याप्त वेतन के। 19वीं सदी के अंत में जब औद्योगिक क्रांति अपने चरम पर थी, तब मजदूरों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। ऐसे समय में उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाई और 8 घंटे कार्य दिवस की मांग की। यह मांग धीरे-धीरे एक बड़े आंदोलन में बदल गई, जिसने पूरी दुनिया को प्रभावित किया। आज जो हमें 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे अपने लिए का सिद्धांत मिलता है, वह इन्हीं संघर्षों की देन है।

भारत में मजदूरों की स्थिति भी अलग नहीं रही। आजादी से पहले और उसके बाद भी मजदूर वर्ग ने कई कठिनाइयों का सामना किया। 1 मई 1923 को भारत में पहली बार मजदूर दिवस मनाया गया, जिसने श्रमिक आंदोलनों को एक नई दिशा दी। इसके बाद धीरे-धीरे मजदूरों के अधिकारों के लिए कानून बनाए गए, जिनमें न्यूनतम मजदूरी, कार्य समय, सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। लेकिन कागजों पर बने ये नियम आज भी पूरी तरह जमीन पर लागू नहीं हो पाए हैं।

आज के समय में भी मजदूरों की स्थिति पूरी तरह संतोषजनक नहीं कही जा सकती। खासकर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को आज भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्हें नियमित रोजगार नहीं मिलता, वेतन अस्थिर होता है और सामाजिक सुरक्षा का अभाव रहता है। निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को देखें तो वे कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, लेकिन उनके पास न तो उचित सुरक्षा उपकरण होते हैं और न ही स्वास्थ्य सुविधाएं।

ऊंची-ऊंची इमारतों के निर्माण में मजदूरों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। वे तपती धूप में, कड़कती सर्दी में और कभी-कभी बारिश में भी लगातार काम करते हैं। उनके बिना शहरों का विकास संभव ही नहीं है। लेकिन इन्हीं इमारतों के बनने के बाद अक्सर मजदूरों को वहां रहने का अधिकार नहीं मिलता। वे झुग्गियों या अस्थायी बस्तियों में रहने को मजबूर होते हैं, जहां बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव होता है।

दल बदल कानून की आड़ में दल बदल

सनत जैन

भारत में इस समय संविधान, कानूनों और नियमों का उपयोग गैर कानूनी एवं अनैतिक तरीके से हो रहा है। संविधान, नियम और कानून का पालन कराने वाले जो लोग कुर्सियों पर विराजमान हैं, वह इन कानूनो का दुरुपयोग करने वालों का संरक्षण कर रहे हैं। जिसके कारण नियम और कानूनो को लेकर आम आदमी का विश्वास धीरे-धीरे खत्म होता चला जा रहा है। यह देश के लिए एक चिंताजनक स्थिति है। भारत में दल बदल कानून इसलिए बनाया गया था, ताकि राजनीतिक दलों में जो लोग किसी पार्टी और विचारधारा से चुनाव जीतकर आते हैं। वह दल बदल करके अपने निजी लाभ के लिए अनैतिक काम न करने पाएं। उसको रोकने 1985 में संविधान में 52वां संशोधन करके दल बदल कानून बनाया गया था।

इस कानून में विभाजन, मर्जर, विलय जैसी स्थितियों को परिभाषित किया गया था। 2003 में संविधान में 91 संशोधन के जरिए पुन: संशोधन करना पड़ा। विलय को पुन: परिभाषित किया गया। नियम और कानून में संविधान में संशोधन के बाद भी दल बदल बड़े पैमाने पर होता रहा। 2014 के बाद दल बदल की घटनाएं और भी तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो गईं। आज दल बदल कानून एक ऐसा कानून बन गया है, जिसकी आड़ में बड़े पैमाने पर दल बदल हो रहा है। राजनीति में भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी को बढ़ा दिया है।

सांसदों और विधायकों के संसद और विधानसभा में अभिव्यक्ति के अधिकार को सीमित कर दिया है। निर्वाचित सांसद या विधायक किसी बिल पर सहमत नहीं हों, उसे खुलकर बहस में भाग लेने या मतदान करने की अनुमति नहीं होती है। पार्टी लाइन के विरोध में मतदान करना चाहेगा, तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। दल बदल कानून के अंतर्गत निर्वाचित सांसदों और विधायकों की अपने मतदाताओं और अपने कर्तव्यों को लेकर अपनी राय जाहिर करने का अधिकार भी खत्म हो गया है। अब



पार्टी तय करती है, सांसदों और विधायकों को पार्टी लाइन पर ही मतदान करना होगा, अन्यथा उसकी सदस्यता चली जाएगी। जिसके कारण दल बदल कानून भारतीय लोकतंत्र और भारतीय संविधान का काला कानून बन गया है। कानून और नियम तभी तक स्वीकार्य होते हैं, जब समाज में नैतिकता होती है। यदि नागरिक, नेता, अधिकारी और जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है, वह नैतिक और जिम्मेदार नहीं होंगे। जिस तरह से पिछले तीन-चार दशकों में नैतिकता का स्थान अब अनैतिकता ने ले लिया है। जो जीता वही सिकंदर की तर्ज पर नियम और कानूनो का दुरुपयोग शुरू हुआ है। उसके बाद स्थितियां बद से बदतर होती चली जा रही हैं। संविधान ने न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान पर रखा था।

न्यायपालिका के पास सीधे कोई अधिकार नहीं है। कानून बनाने की विधायिका को, कार्यपालिका को यह जिम्मेदारी दी गई, जो भी नियम-कानून बनाए जाते हैं, उनके अनुसार कार्यपालिका की जिम्मेदारी तय है। संविधान ने न्यायपालिका को दोनों संवैधानिक संस्थाओं के कार्यों की समीक्षा का अधिकार दिया। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षण, नियम, कानून और कायदे से कार्यपालिका और विधायिका काम कर रही है, या नहीं। इसकी समीक्षा का अधिकार न्यायपालिका के पास है। न्यायपालिका के आदेशों का पालन करना कार्यपालिका और विधायिका के लिए अनिवार्य है। पिछले कुछ वर्षों में न्यायपालिका संविधान के प्रति अपनी जवाबदेही और कर्तव्यों को लेकर कमजोर होती हुई दिख रही है। न्यायपालिका में भी सरकारी दबाव, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, जवाबदेही का अभाव स्पष्ट रूप से दिखने लगा है। जिसके कारण अब न्यायपालिका के प्रति लोगों का वह विश्वास खत्म हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार अपने हर निर्णय को सही ठहराती है। जब उनका विरोध होता है, तब सरकार कहती है न्यायपालिका चले जाओ।

न्यायपालिका जाने पर भी वर्षों तक न्याय नहीं मिलता है। तारीख पर तारीख मिलती रहती है, जो फैसले आ रहे हैं, वह आधे अधूरे होते हैं। जिसके कारण कानून के प्रति आम आदमी को विश्वास नहीं रहा। दल बदल कानून का जिस तरह से दुरुपयोग हुआ है। आसंदी में बैठे हुए अध्यक्ष एवं सभापति जो बहुमत के आधार पर चुने जाते हैं। उन्होंने अपने अधिकारों का पार्टी के हितों के लिए दुरुपयोग किया है। सही समय पर फैसला नहीं दिया, फैसला दिया तो वह नियम और कानून के अनुसार नहीं था। जिसकी लाठी, उसकी भैंस का जो कानून हजारों लाखों वर्ष से चला आ रहा था, वही कानून अब लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी स्थान ले रहा है। दल बदल कानून में आसंदी अपनी राजनीतिक निष्ठा के अनुसार अलग-अलग निर्णय देती हैं। कुछ इसी तरह की स्थिति हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की भी देखने को मिलने लगी है। महाराष्ट्र में जब दल बदल हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के निर्णय और दल बदल को गैर संवैधानिक बताया। इसके बाद भी सरकार चलती रही।

महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष के निर्णय की न्यायिक समीक्षा समय पर नहीं हुई। दल बदलू सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। उसके बाद दूसरा चुनाव भी हो गया। आम आदमी पार्टी के 7 सांसदों ने राज्यसभा में आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर भाजपा में चले गए है। जैसे ही उन्होंने दल बदलने का आवेदन किया। राज्यसभा के सभापति ने बिना किसी सुनवाई के उन्हें भाजपा का सांसद मान लिया।

आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में है, उसके विधायक हैं राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, राज्यसभा के सभापति ने यह देखने की जहमत नहीं उठाई, दल बदल कानून में नियमों का पालन हुआ है, या नहीं, जबकि आम आदमी पार्टी ने अपनी आपत्ति राज्यसभा सचिवालय को सौंप दी थी। वर्तमान हालात को देखते हुए यही कहा जा सकता है। संविधान, लोकतंत्र, कानून का राज, लट्ठ तंत्र के अधीन है। जिसके पास लाठी की ताकत है, कानून उसका ही चलेगा। विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो या कार्य पालिका हो, लाठी की ताकत से सभी को नियंत्रित होना ही होता है। संविधान की लाठी कमजोर हो गई है। सत्ता पक्ष की लाठी ज्यादा मजबूत है। जो मजबूत है, वहीं शासन कर सकता है। अनादि काल से यही सत्य देखते आ रहे हैं, यही सत्य अंत तक बना रहेगा।

आज का इतिहास

1778 अमेरिकी क्रांति: कुटिल बिलेट की लड़ाई हेटबोरो, पेनसिल्वेनिया में शुरू हुई।
1781 सम्राट जोज़ेफ़ द्वितीय जनसंख्या के संरक्षण को कम कर दिया।
1786 मोजार्ट के ओपेरा विवाह की शादी वियना में प्रीमियर हुई।
1794 पिछले साल स्पेन की बलोउ की लड़ाई में अपनी जीत के साथ पाइरेनिस-फ्रांस का युद्ध लगभग सभी भूमि को फिर से हासिल कर लिया जो वह स्पेन से हार गया था।
1822 जॉन फिलिप्स बोस्टन के पहले मेयर बने।
1834 बेल्जियन संसद ने रेलवे कानूनों को स्वीकार किया
1840 विश्व का पहला डाक टिकट ग्रेट ब्रिटेन में जारी किया गया था, जिसके ऊपर ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का चित्र छपा था। यह डाक टिकट काले रंग में एक छोटे से चौकोर काग़ज़ पर छपा था और उसकी कीमत एक पेनी रखी गई थी।
1844 हांगकांग पुलिस बल दुनिया की दूसरी और एशिया की पहली आधुनिक पुलिस बल की स्थापना की गयी।
1850 जॉन गेयरी सैन फ्रांसिस्को के पहले मेयर बने।
1851 द ग्रेट एग्जिबिशन, पहली बार दुनिया का मेला, लंदन का हाइड पार्क खोला गया।
1865 ब्राजील, उरुग्वे और अर्जेंटीना ने ट्रिपल एलायंस के युद्ध में परागवे के खिलाफ एक संधि बनाने के लिए एक संधि पर हस्ताक्षर किए।
1873 पहला यूएस पोस्टल डाक कार्ड जारी किया गया।
1886 अमरीका की मज़दूर यूनियनों नें काम का समय 8 घंटे से ज़्यादा न रखे जाने के लिए हड़ताल की थी। तब से पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मज़दूर दिवस मनाने की शुरूआत हुई।
1895 दुन्देला फुटबॉल, खेल और बेलफास्ट में एसोसिएशन क्लब का गठन किया गया।
1897 रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने हिंदू मठ के आदेश रामकृष्ण मठ के मानवतावादी समकक्ष के रूप में की थी।
1898 कमोडोर के तहत अमेरिकी एशियाई स्क्वाड्रन जॉर्ज डेवी ने स्पेनिश-अमेरिकी युद्ध की पहली सगाई मनीला बे के एडमिरल पेट्रीसियो मोंतोजो अटे लड़ाई के तहत स्पेनिश प्रशांत स्क्वाड्रन को हराया।
1914 अमेरिकी कार निर्माता कंपनी फोर्ड मोटर्स पहली कंपनी बनी जिसने अपने कर्मचारियों के लिए आठ घंटे काम करने का नियम लागू किया।
1941 अभिनेता और निर्देशक ओर्सन वेल्स द्वारा एक व्यापक रूप से प्रशंसित फिल्म सिटीजन केन का प्रीमियर हुआ।

पंजाब से दिल्ली तक सियासी 'सुनामी': संकट में आम आदमी पार्टी

योगेश कुमार गोयल

भारत की समकालीन राजनीति में शायद ही कोई घटना इतनी तेजी से राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में आई हो, जितनी राघव चड्ढा सहित सात राज्यसभा सांसदों के आम आदमी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से आई है। राघव चड्ढा सहित 7 सांसदों का भाजपा में विलय केवल एक खबर नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के 15 साल के इतिहास का सबसे बड़ा ब्लैकआउट है। भारतीय राजनीति के क्षितिज पर यह घटनाक्रम एक बड़े 'पॉलिटिकल अर्थक्वेक' के रूप में दर्ज हो गया है। आम आदमी पार्टी (आप) के 'पोस्टर बॉय' माने जाने वाले राघव चड्ढा सहित राज्यसभा के 7 सांसदों का एक साथ पाला बदलकर भाजपा में शामिल होना न केवल 'आप' के लिए एक अस्तित्वगत संकट है बल्कि यह देश की राजनीति की दिशा और दशा बदलने वाला घटनाक्रम भी है। यह सिर्फ दल-बदल नहीं बल्कि सत्ता, विचारधारा और राजनीतिक रणनीति के बीच गहरे संघर्ष का संकेत है। जब राज्यसभा में पार्टी के कुल 10 में से 7 सांसद (दो-तिहाई बहुमत) एक साथ अलग होकर भाजपा में विलय करने का निर्णय लेते हैं तो यह दलबदल नहीं, एक वैचारिक और संगठनात्मक विद्रोह का प्रतीक बन जाता है। यह घटनाक्रम ऐसे समय में हुआ है जब भारतीय राजनीति 2027 के बड़े चुनावी चक्र की ओर बढ़ रही है। ऐसे में इस घटनाक्रम ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या 'आप' का 'पंजाब किला' अब ढ़हने के कगार पर है? क्या 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव की पटकथा अभी से लिखी जा चुकी है? और सबसे बड़ा प्रश्न कि क्या यह 'आप' के पतन की शुरुआत है या फिर एक अस्थायी राजनीतिक झटका?

आम आदमी पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम को केवल राजनीतिक असहमति नहीं बल्कि लोकतंत्र पर सुनियोजित प्रहार करार दिया है। पार्टी नेतृत्व का स्पष्ट आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियों के भय, दबाव और राजनीतिक प्रलोभनों के माध्यम से उसके सांसदों को तोड़ा गया, जिसे वह संस्थागत दुरुपयोग की श्रेणी में रखती है। यह आरोप भारतीय राजनीति में सत्ता बनाम विपक्ष की उस पुरानी बहस को फिर जीवित कर देता है, जहां नैतिकता और रणनीति आमने-सामने खड़ी दिखाई देती हैं। संवैधानिक दृष्टि से यह कदम और भी दिलचस्प हो जाता है। दलबदल विरोधी कानून की तकनीकी बारीकी (दो-तिहाई सदस्यों के एक साथ अलग होने की शर्त) का उपयोग करते हुए राघव चड्ढ़ा के नेतृत्व में सात सांसदों का भाजपा में विलय यह संकेत देता है कि यह केवल भावनात्मक निर्णय नहीं बल्कि गहन कानूनी सलाह और रणनीतिक योजना का परिणाम था। सबसे गंभीर आघात वैचारिक



स्तर पर है। जब भीतर से ही यह स्वर उठे कि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से भटक गई है तो यह केवल संगठनात्मक संकट नहीं बल्कि पहचान के संकट का संकेत बन जाता है और यही चुनौती 'आप' के लिए सबसे कठिन परीक्षा है।

पंजाब की राजनीति में उठी यह हलचल महज दल-बदल नहीं बल्कि सत्ता समीकरणों के पुनर्गठन का संकेत है। इस विद्रोह का सबसे गहरा असर पंजाब की सियासत पर पड़ना तय है। राज्यसभा में पंजाब का प्रतिनिधित्व करने वाले चेहरे (हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, संजीव अरोड़ा और विक्रमजीत सिंह साहनी) का पार्टी से अलग होना 'आप' की उस सामाजिक पकड़ को कमजोर करता है, जो विविध वर्गों के प्रतिनिधित्व से बनी थी। यह बदलाव केवल संख्या का नहीं बल्कि भरोसे और प्रभाव का क्षरण है। सबसे बड़ी चुनौती भगवंत मान के सामने है। यह उनके नेतृत्व और राजनीतिक संतुलन की सीधी परीक्षा है। राघव चड्ढ़ा को लंबे समय तक सरकार और संगठन के बीच रणनीतिक कड़ी माना जाता रहा, उनके हटने से यह संतुलन डगमगाता दिख रहा है। दूसरी ओर, भाजपा इस घटनाक्रम को अवसर में बदलने की कोशिश में है। भाजपा पंजाब में हमेशा से एक छोटा भाई (अकाली दल के साथ) बनकर रही है लेकिन 7 सांसदों के आने से, जिनमें सिखों और उद्योगपतियों का प्रतिनिधित्व है, भाजपा अब 2027 में अकेले दम पर सरकार बनाने का सपना देख रही है। अब तक सहयोगी राजनीति तक सीमित रही भाजपा अब पंजाब में स्वतंत्र शक्ति बनने की दिशा में आक्रामक कदम बढ़ाती दिख रही है और 2027 का रण अब पहले से कहीं अधिक खुला और अनिश्चित हो गया है।

इतिहास गवाह है कि क्षेत्रीय दल जब ऐसे बड़े विद्रोह का सामना करते हैं तो अक्सर वे या तो बिखर जाते हैं या फिर सिमटकर रह जाते हैं लेकिन आप की स्थिति थोड़ी भिन्न है। इसका सबसे बड़ा कारण है अरविंद केजरीवाल का व्यक्तित्व। आम आदमी पार्टी का आधार अरविंद केजरीवाल की 'व्यक्तिगत ब्रांडिंग' पर टिका है। जब तक दिल्ली और पंजाब जैसे अहम राज्यों में उनका जनाधार सुरक्षित है, तब तक 'आप' का पूर्ण पतन लगभग असंभव प्रतीत होता है। इसके समानांतर, 'आप' की ताकत उसका विकसित कैडर ढांचा है। आप ने पिछले एक दशक में एक मजबूत कैडर तैयार किया है। हालांकि शीर्ष स्तर पर योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और अब राघव चड्ढा जैसे प्रमुख चेहरों का अलग होना पार्टी को बड़ा झटका देता है लेकिन जमीनी कार्यकर्ता अब भी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हैं। एक वैकल्पिक, जनोन्मुख और व्यवस्था-विरोधी नेता की केजरीवाल की छवि अब भी पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी बनी हुई है।

राष्ट्रीय राजनीति के व्यापक परिप्रेक्ष्य में यह घटनाक्रम सत्ता-संतुलन को निर्णायक रूप से प्रभावित करता है। राज्यसभा में सात सांसदों के जुड़ने से भाजपा की स्थिति और सुदृढ़ हुई है, जिससे अब महत्वपूर्ण विधेयकों के पारित होने में उसकी छोटे दलों पर निर्भर रहने की बाध्यता कम हो गई है। इसके विपरीत, विपक्षी गठबंधन के लिए यह स्पष्ट झटका है क्योंकि 'आप' इस गठबंधन की मुखर आवाज रही है। सबसे गंभीर आघात 'आप' की वैचारिक विश्वसनीयता पर पड़ा है। जो पार्टी 'ईमानदार राजनीति' को अपनी पहचान मानती रही, उसी के भीतर से वैचारिक विचलन और आरोपों का उठना उसके नैरेटिव को कमजोर करता है। यह स्थिति नेतृत्व शैली पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है, लगातार बड़े चेहरों का अलग होना इस ओर संकेत करता है कि संवाद की कमी और निर्णय प्रक्रिया का केंद्रीकरण आंतरिक असंतोष को जन्म दे रहा है। राष्ट्रीय विस्तार की महत्वाकांक्षा पर भी इसका प्रभाव पड़ना तय है। दिल्ली और पंजाब से आगे बढ़ने की जो रणनीति थी, वह अब धीमी पड़नी तय है, विशेषकर तब, जब पंजाब, जो 'आप' का सबसे मजबूत गढ़ है, स्वयं इस राजनीतिक भूकंप के केंद्र में आ खड़ा हुआ है।

यह कहना जल्दबाजी होगी कि 7 सांसदों के जाने से आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी। राजनीति में रिक्तियां हमेशा भर दी जाती हैं। हालांकि यह निश्चित है कि आप अब अपनी सबसे कठिन अग्निपरीक्षा से गुजर रही है। यदि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान अगले कुछ महीनों में पंजाब और दिल्ली के कैडर को एकजुट रखने में विफल रहे तो 2027 का चुनाव उनके लिए एक राजनीतिक ढ़लान साबित हो सकता है। दूसरी ओर, भाजपा ने इस 'मास्टरस्ट्रोक' के जरिए यह संदेश दे दिया है कि वह दिल्ली और पंजाब की सत्ता के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। बहरहाल, 'आप' के लिए चुनौती अब केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि अपने अस्तित्व और साख को बचाए रखना है।

एग्जिट पोल्स: क्या वास्तव में मतदाता की चुप्पी को कोई पढ़ पाएगा?

विनोद पाठक

पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुद्दुचेरी के एग्जिट पोल्स सामने आते ही भारतीय राजनीति में एक बार फिर वही पुराना द्वंद्व उभर आया है, क्या ये आंकड़े सच के करीब हैं या फिर यह केवल एक अनुमानित राजनीतिक कथा है? इस बार का चुनाव इसलिए भी खास है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की रणनीति, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की साख, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन का शासन मॉडल और राहुल गांधी की राजनीतिक दिशा, सभी एक साथ कसौटी पर हैं। पश्चिम बंगाल में एग्जिट पोल्स का गणित जितना रोचक है, उतना ही उलझा हुआ भी। इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया तृणमूल कांग्रेस को लगभग 158 से 170 सीटें देता दिख रहा है, जबकि भाजपा को 110 से 120 के बीच रखा गया है। वहीं एबीपी सी वोटर का अनुमान भी लगभग इसी के आसपास है, जहां तृणमूल 152 से 164 और भाजपा 109 से 121 के बीच बताई गई है। इसके उलट रिपब्लिक-सीएनएक्स का सर्वे भाजपा को 138 से 148 सीटों के साथ आगे दिखाता है और तृणमूल को 128 से 138 के बीच रखता है। इतने भिन्न आंकड़े एक ही राज्य के लिए क्या यह बताता है कि जमीन पर मुकाबला वास्तव में बेहद करीबी है या यह कि एग्जिट पोल्स अभी भी बंगाल की जटिल राजनीति को ठीक से समझ नहीं पा रहे? तमिलनाडु में तस्वीर अपेक्षाकृत साफ नजर आती है, जहां लगभग सभी एजेंसियां एमके स्टालिन के नेतृत्व में द्रमुक गठबंधन की वापसी की ओर इशारा कर रही हैं। इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया द्रमुक+ को 175 से 190 सीटों तक ले जाता दिख रहा है, जबकि अन्नाद्रमुक+ को 40 से 55 के बीच सीमित करता है। न्यूज 18-आईपीएसओएस भी लगभग इसी रेंज में द्रमुक+ को 160 से 180 और विपक्ष को 50 से 70 सीटों के बीच रखता है, लेकिन क्या यह स्पष्ट बढ़त वास्तव में जनसमर्थन का प्रतिबिंब है या फिर विपक्ष की कमजोर चुनौती का परिणाम? असम में एग्जिट पोल्स भाजपा के पक्ष में झुकते नजर आते हैं। इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया एनडीए को 75 से 85 सीटों तक पहुंचाता है, जबकि कांग्रेस-नीत गठबंधन को 40 से 50 के बीच रखता है। रिपब्लिक-सीएनएक्स का अनुमान भी लगभग इसी दिशा में है, जहां एनडीए को 74 से 84 सीटें और कांग्रेस को 45 से 55 सीटों के बीच दिखाया गया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की रणनीति यहां असरदार दिखती है, लेकिन क्या यह बढ़त वाकई इतनी ठोस है कि नतीजों में भी वैसी ही दिखाई दे? केरल में एग्जिट पोल्स एक दिलचस्प तस्वीर पेश करते हैं, जहां मुकाबला बेहद करीबी बताया जा रहा है, लेकिन झुकाव कांग्रेस-नीत यूडीएफ की ओर है। एबीपीड्डूसी वोटर यूडीएफ को 70 से 80 सीटों के बीच और एलडीएफ को 60 से 70 के बीच रखता है, जबकि इंडिया टुडे-एक्सिस माय इंडिया भी यूडीएफ को 68 से 75 और एलडीएफ को 65 से 72 के बीच दिखाता है। राहुल गांधी की सक्रियता के बीच यह सवाल उठता है, क्या केरल अपनी पारंपरिक सत्ता परिवर्तन की राजनीति पर लौट रहा है या यह केवल एक अनुमान है जो नतीजों में बदल भी सकता है और नहीं भी? पुद्दुचेरी में एग्जिट पोल्स किसी एक पक्ष को स्पष्ट बहुमत नहीं देते। रिपब्लिक-सीएनएक्स एनडीए को 16 से 20 सीटों तक और कांग्रेस गठबंधन को 10 से 14 के बीच दिखाता है, जबकि सी वोटर का अनुमान एनडीए को 14 से 18 और कांग्रेस+ को 12 से 16 सीटों के बीच रखता है। यहां सवाल यह है कि क्या छोटे राज्यों में एग्जिट पोल्स की अनिश्चितता और बढ़ जाती है, जहां स्थानीय समीकरण ज्यादा निर्णायक होते हैं? एग्जिट पोल्स का इतिहास खुद इनके प्रति सावधानी बरतने की सलाह देता है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में एक्सिस मार इंडिया जैसी एजेंसियों ने एनडीए की जीत का काफी हद तक सही अनुमान लगाया था, लेकिन 2021 के पश्चिम बंगाल चुनाव में लगभग सभी एजेंसियां तृणमूल कांग्रेस की वास्तविक बढ़त को पकड़ने में विफल रहीं तो क्या यह मान लिया जाए कि जब स्पष्ट लहर होती है, तब एग्जिट पोल्स सही साबित होते हैं, और जब मुकाबला जटिल होता है तब ये चूक जाते हैं? इन आंकड़ों के बीच कुछ असहज सवाल भी उभरते हैं, क्या एग्जिट पोल्स वास्तव में मतदाता की चुप्पी को पढ़ पाते हैं? क्या ग्रामीण भारत की आवाज इनमें पूरी तरह शामिल होती है? क्या ये आंकड़े निष्पक्ष विश्लेषण हैं, या राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने का एक माध्यम बन चुके हैं? इन पांच राज्यों के एग्जिट पोल्स एक अधूरी कहानी ही कहते हैं। वे संकेत देते हैं, लेकिन निर्णय नहीं सुनाते। भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि वह हर अनुमान को चुनौती देता है। अंतिम सच वही होता है, जो मतगणना के दिन सामने आता है।

बंगाल में धर्म पथ पर खूब चले मोदी और शाह

नीरज कुमार दुबे

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत के लिए जी-तोड़ मेहनत करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर चुनाव प्रचार तो किया ही साथ ही पूजा पाठ में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान वाले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में बाबा श्री काशी विश्वनाथ का पूजन कर रहे थे। जबकि मतदान से एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भगवान श्री सोमनाथ का पूजन किया। यही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा में जाकर मिलने वाली हुगली नदी में नौका यात्रा और पूजन किया तो वहीं अमित शाह ने हुगली नदी और बंगाल की खाड़ी के पवित्र संगम पर स्थित गंगासागर का दर्शन और पूजन किया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतुआ समुदाय के मुख्य मंदिर ठाकुरबाड़ी और राजधानी कोलकाता के ऐतिहासिक ठनठनिया काली मंदिर में पूजा-अर्चना की तो अमित शाह ने कपिल मुनि आश्रम में महर्षि कपिल का पूजन कर देशवासियों के कल्याण की कामना की।

बंगाल में मतदान वाले दिन प्रधानमंत्री का श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने का अधिक महत्व इसलिए है क्योंकि काशी (वाराणसी) को बंगालियों का दूसरा घर या सांस्कृतिक रूप से बंगाल के बहुत करीब माना जाता है। सदियों से बंगाली तीर्थयात्री, विद्वान और साधु-संत काशी आते रहे हैं, साथ ही कई बंगाली जमींदारों और राजाओं ने काशी में घाटों और मंदिरों का निर्माण करवाया। यही नहीं, वाराणसी में दशाश्वमेध घाट के पास स्थित %बंगाली टोला% क्षेत्र में बंगाली समुदाय की घनी आबादी है, जहाँ बंगाली संस्कृति, भाषा और खान-पान का गहरा असर देखने को मिलता है। वहीं गुजरात के श्री सोमनाथ में त्रिवेणी संगम (कपिला, हिरन और सरस्वती) के पास चंद्रभागा शक्तिपीठ स्थित है, जो बंगाली भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है।

प्रधानमंत्री मोदी की ओर से हुगली नदी पर किये गये नौका विहार का भी खास महत्व है। हुगली को %आदि गंगा% के रूप में पूजा जाता है। बंगाल के लोगों के लिए हुगली का महत्व वैसा ही है जैसा उत्तर भारत में गंगा का है। नरेंद्र मोदी ने 2014 में जब



लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए वाराणसी को चुना था तो उन्होंने सबसे पहले यही कहा था कि मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। इसी तरह खुद को %गंगापुत्र% कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल चुनावों के बीच हुगली को मां गंगा कहकर संबोधित किया और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त की। इससे उन्होंने अपनी छवि को बंगाल की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं के साथ जोड़ा। प्रधानमंत्री ने हुगली के किनारे समय बिताकर और बेलूर मठ जैसे आध्यात्मिक केंद्रों की यात्रा कर यह दिखाने की कोशिश भी की कि उनकी पार्टी बंगाल की जड़ों और विरासत का सम्मान करती है।

वहीं अमित शाह की गंगा सागर यात्रा भी काफी प्रभावशाली रही। सदियों से यह कहा जाता रहा है कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। अमित शाह ने इस यात्रा के जरिए भाजपा को बंगाल की जड़ों से जोड़ा। ऐतिहासिक कपिल मुनि आश्रम में पूजा-अर्चना कर उन्होंने बंगाली धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया। उन्होंने गंगा को गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भारत को जोड़ने वाली एक आध्यात्मिक कड़ी बताया, जिससे भाजपा ने यह संदेश दिया कि बंगाल की संस्कृति पूरे भारत के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। साथ ही अमित शाह ने गंगा सागर में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देकर धर्म और राष्ट्रवाद को एक साथ जोड़ा, जो भाजपा की चुनावी रणनीति का मुख्य आधार रहा है।

इसके अलावा, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राज्य की राजधानी कोलकाता के ऐतिहासिक ठनठनिया काली मंदिर में पूजा-अर्चना कर भी बड़ा संदेश दिया। उत्तरी कोलकाता की प्रमुख उत्तर-दक्षिण सड़क बिधान सरानी पर स्थित, ठनठनिया काली मंदिर की स्थापना 1703 में उदय नारायण ब्रह्मचारी ने उस भूमि पर की थी, जहां उस समय श्मशान घाट हुआ करता था। इस मंदिर में मां सिद्धेश्वरी की पूजा की जाती है। यहाँ की एक विशिष्ट परंपरा मांसाहारी प्रसाद चढ़ाने की है। इस मंदिर में पूजा कर प्रधानमंत्री ने यह संदेश दिया कि भाजपा बंगाल की विविध खान-पान और धार्मिक परंपराओं को स्वीकार करती है और उनका सम्मान करती है, जिससे विरोधियों के शाकाहारी थोपने के आरोपों का जवाब दिया गया। साथ ही यह मंदिर रामकृष्ण परमहंस से भी जुड़ा है, जो यहाँ अक्सर भजन गाने आते थे। इस यात्रा के जरिए भाजपा ने खुद को बंगाल के पुनर्जागरण और आध्यात्मिक महापुरुषों की विरासत से भी जोड़ा।

वहीं उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुरनगर में मतुआ महासंघ के मुख्य मंदिर ठाकुरबाड़ी में दर्शन कर प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल के दलित (नामशुद्र) समाज के प्रति सम्मान व्यक्त किया। पीएम मोदी ने 2021 में बांग्लादेश स्थित मतुआ समुदाय के जन्मस्थान ओराकांडी की भी यात्रा की थी। ठाकुरबाड़ी की वर्तमान यात्रा उस निरंतरता को दर्शाती है। मतुआ मतदाता कम से कम 34 विधानसभा सीटों और बांग्लादेश सीमा के करीब स्थित दो दर्जन अन्य सीटों को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। उल्लेखनीय है कि हरिचंद ठाकुर द्वारा 19वीं शताब्दी में स्थापित मतुआ महासंघ एक सामाजिक-धार्मिक आंदोलन है, जिसने ऐतिहासिक रूप से शिक्षा और सामाजिक सुधार के माध्यम से नामशुद्र समुदाय के उत्थान के लिए काम किया है।

बहरहाल, पश्चिम बंगाल चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये धार्मिक यात्राएं केवल व्यक्तिगत आस्था तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे एक व्यापक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा थीं। इन यात्राओं के माध्यम से भाजपा ने बंगाल की सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक जड़ों से जुड़ने का प्रयास किया, ताकि खुद को बाहरी पार्टी की बजाय एक संवेदनशील और जुड़ी हुई शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया जा सके। आस्था, संस्कृति और राजनीति के इस संगम ने यह स्पष्ट कर दिया कि आधुनिक भारतीय चुनावों में प्रतीकवाद और भावनात्मक जुड़ाव उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने विकास और नीतिगत मुद्दे।

चौधरी के 'नया चेहरा और नया नारा' से बंगाल में चल गई भाजपा की लहर

कमलेश पांडे

बिहार में नए मुख्यमंत्री पद पर सम्राट चौधरी के चयन ने भाजपा को एक नया चेहरा और नया नारा दिया है, जिसे पार्टी पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में केंद्र में लेकर चल रही है। इसी वजह से बिहार के नए प्रमुख चेहरे के इस चयन से बंगाल में भी भाजपा की लहर की बात तेज़ी से चलने लगी है। चूंकि बिहार में सम्राट चौधरी का महत्व निर्द्वन्द है, इसलिए पश्चिम बंगाल के लोगों में भाजपा के प्रति विश्वास और गहरा हुआ। उल्लेखनीय है कि बिहार में नीतीश कुमार के बाद भाजपा ने पहली बार अपने प्रत्यक्ष नेता को मुख्यमंत्री बनाकर संकेत दिया है कि पार्टी अब एनडीए के नेतृत्व को भी भाजपा के नाम से बेचेगी।

बता दें कि तारापुर की सियासत को लोककल्याण कारी दिशा देने वाले पूर्व स्वास्थ्य मंत्री शकुनि चौधरी के यशस्वी पुत्र सम्राट चौधरी कुशवाहा (कोईरी/ओबीसी) समाज से हैं; लेकिन सवर्णों के बीच बहुत लोकप्रिय हैं। तारापुर से परवत्ता के लोग इसकी गवाही देते हैं। इससे भाजपा ने बिहार के लव कुश (कुर्मी-कुशवाहा) समीकरण को अपने पक्ष में खींचने की कोशिश की है, जो राज्य की 50-60 सीटों पर असर डालता माना जाता है। साथ ही पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी की तरह कोई भी बड़ा सवर्ण नेता व्यक्तिगत रूप से इनका विरोधी नहीं हो सकता है। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की पूर्वी भारत की राजनीति को असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्वशर्मा से भी बड़ा चेहरा बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के रूप में मिल गया है, जिन्हें दिल्ली में भाजपा की लहर चलवाने और यूपी में भाजपा को मजबूत बनवाने के नजरिए से आगे बढ़ाया गया है। इसके पीछे बिहार के नौकरशाही की फीडबैक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि उनकी राजनीतिक छवि बेदाग है, इस मीडिया और राजनीतिक प्रायोजित मामलों को छोड़ दिया जाए तो।



सम्राट चौधरी अपने उपमुख्यमंत्री पद के बाद पश्चिम बंगाल में भी भाजपा के प्रमुख प्रचारक के रूप में सक्रिय हुए हैं; उन्होंने बंगाल के चुनावी दौर में बार बार दावा किया है कि बंगाल में लोग बदलाव के लिए तैयार हैं और भाजपा की सरकार बनेगी। चौधरी ने बर्बरता, घुसपैठ, रोज़गार और सोनार बंगाल की वापसी जैसे मुद्दे उठाकर बिहार मॉडल के नाम पर एक नयी राजनीतिक कहानी बंगाल में बेचनी शुरू की है; इससे भाजपा को एक नया नारा और एक नया चेहरा मिल गया है, जिसे मीडिया व जनता ने लहर की तरह पेश किया है।

बिहार में ओबीसी केंद्रित और सवर्ण, दलित, अल्पसंख्यक समर्थित मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के उभार के बाद भाजपा तर्क दे रही है कि अब यह गैर संस्कृतिक (संयुक्त तरह के राष्ट्रवादी ओबीसी) चेहरा बंगाल में भी विपक्षी भावनाओं को एकजुट कर सकता है। दोनों राज्यों में भाजपा एक ही नारा बेच रही है: पुरानी सत्ता संरचना का अंत और नई नेतृत्व पीढ़ी की शुरुआत; इसी जोड़ को देखते हुए बिहार में सम्राट के चयन को पश्चिम बंगाल में भाजपा की लहर का तर्क प्रतीक माना जा रहा है।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में सम्राट चौधरी भाजपा के एक प्रमुख स्टार प्रचारक और मिशन बंगाल के आगे बढ़े चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। उनकी भूमिका मुख्यत: तीन तरह की है- नारा निर्माता, बिहारी बंगाल जुड़ाव बनाने वाला चेहरा, और ममता सरकार की आलोचना के लिए उग्र आवाज़। उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में जिम्मेदारी मिली, क्योंकि भाजपा ने पश्चिम बंगाल के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है, जिसमें बिहार से सम्राट चौधरी को विशेष प्राथमिकता दी गई है; वे बिहार के उन चुनिंदा नेताओं में हैं जिन्हें बंगाल में बड़ा चुनावी जिम्मा सौंपा गया है। उन्हें बंगाल के कई चरणों में रैलियों और चुनावी सभाओं के लिए तैयार किया गया है, खासकर 23 व 29 अप्रैल के चरणों में जहां भाजपा जीत सुनिश्चित करने की तैयारी कर रही है।

बिहार के उपमुख्यमंत्री होने के नाते चौधरी बिहार मूल के मतदाताओं (खासकर हावड़ा और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले मजदूर, व्यापारी, कामगार) को निशाना बना रहे हैं, जहां बिहारी समुदाय की संख्या अधिक मानी जाती है। वे बिहार में नौकरी वाला मॉडल (लगभग 50 लाख लोगों को नौकरी/रोज़गार के अवसर) का उदाहरण देकर यह वादा कर रहे हैं कि बंगाल में भी वही तरह का रोज़गार आधारित विकास सोनार बंगाल के नाम से लाया जाएगा।

सम्राट चौधरी ने घुसपैठ, एनआरसी, बंगाली अस्मिता और हिंदू उत्पीड़न जैसे मुद्दों पर खुले आरोप लगाए हैं और कहा है कि भाजपा सत्ता में आकर घुसपैठियों को बाहर करेगी और बंगाली पहचान को फिर से स्थापित करेगी। वे ममता बनर्जी सरकार को अराजक, हिन्दू विरोधी और घुसपैठियों की हिमायती कहकर जनता में बदलाव की भावना जगाने की कोशिश कर रहे हैं, और बार बार दावा कर रहे हैं कि इस बार बंगाल में भाजपा की ही सरकार बनेगी। संक्षेप में कहें तो, सम्राट चौधरी पश्चिम बंगाल में भाजपा के लिए बिहार मॉडल व बदलाव की आवाज़ बनकर आगे बढ़ रहे हैं, जिससे पार्टी को गैर बंगाली (खासकर बिहारी) मतदाताओं से जुड़ने और राष्ट्रवाद घुसपैठ रोज़गार के मुद्दे पर एकीकृत नारा बेचने में मदद मिल रही है।

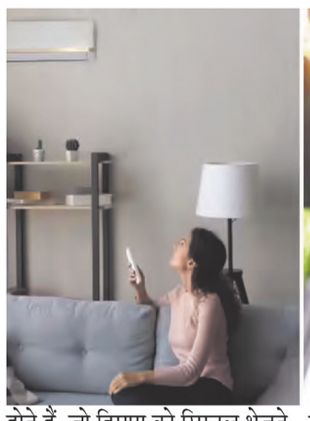
ट्रंप पर हमला मतलब सुरक्षा में भारी चूक

सौरभ वार्ष्णेय

अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में आयोजित व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स डिनर—जो परंपरागत रूप से प्रेस की स्वतंत्रता और सत्ता के बीच संवाद का प्रतीक माना जाता है। इस बार एक भयावह सुरक्षा चूक का गवाह बन गया। जिस आयोजन में पत्रकार, राजनेता और नीति-निर्माता एक मंच पर आते हैं, वहीं गोलियों की आवाज़ ने लोकतंत्र के इस उत्सव को दहशत में बदल दिया। शनिवार रात आयोजित इस कार्यक्रम में एक सशस्त्र हमलावर ने सुरक्षा घेरा तोडने की कोशिश की और गोलीबारी कर दी। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अमेरिकी राष्ट्रपति को तत्काल कार्यक्रम से सुरक्षित बाहर लेकर जाना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति पर हुआ हमला केवल एक व्यक्ति या पद पर आघात नहीं है, बल्कि यह विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक की संस्थाओं, स्थिरता और सुरक्षा व्यवस्था पर सीधा प्रश्नचिन्ह है। अमेरिका जैसे देश, जो वैश्विक स्तर पर लोकतांत्रिक मूल्यों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और कानून के शासन का प्रतिनिधित्व करता है, वहां इस तरह की घटना गहरी चिंता पैदा करती है। सबसे पहले, यह घटना बताती है कि दुनिया के सबसे सशक्त देशों में भी सुरक्षा तंत्र अभेद्य नहीं है। राष्ट्रपति की सुरक्षा को अत्यंत उच्च स्तर का माना जाता है, फिर भी यदि उस पर हमला संभव हो जाता है, तो यह सुरक्षा एजेंसियों की रणनीति और खुफिया तंत्र की समीक्षा की मांग करता है। यह केवल तकनीकी विफलता नहीं, बल्कि संभावित रूप से बढ़ती आंतरिक अस्थिरता का संकेत भी हो सकता है। दूसरा पहलू राजनीतिक ध्रुवीकरण का है। हाल के वर्षों में अमेरिका में वैचारिक विभाजन तीव्र हुआ है। ऐसी परिस्थितियों में हिंसक घटनाएं केवल सुरक्षा की कमी नहीं, बल्कि सामाजिक असंतोष और राजनीतिक कट्टरता के उभार का परिणाम भी हो सकती हैं। यदि लोकतांत्रिक संवाद की जगह आक्रोश और हिंसा ले लेते हैं, तो यह किसी भी लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है। तीसरा, इस घटना के अंतरराष्ट्रीय प्रभाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं। अमेरिका वैश्विक राजनीति का केंद्र है, और वहां की अस्थिरता का असर विश्व अर्थव्यवस्था, कूटनीति और सुरक्षा पर पड़ सकता है। सहयोगी देशों के लिए यह चिंता का विषय है कि क्या अमेरिका अपनी आंतरिक चुनौतियों के बीच वैश्विक नेतृत्व की भूमिका प्रभावी ढंग से निभा पाएगा। हालांकि, यह भी ध्यान देने योग्य है कि लोकतंत्र की असली ताकत उसकी पुनरुत्थान क्षमता में होती है। अमेरिका ने अपने इतिहास में कई संकट देखे हैं—चाहे वह गृहयुद्ध हो, आतंकवादी हमले हों या राजनीतिक उथल-पुथल—और हर बार उसने संस्थाओं को मजबूत करते हुए आगे बढने का प्रयास किया है। यह घटना एक स्पष्ट संदेश देती है कि लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं चलता, बल्कि उसे निरंतर संवाद, सहिष्णुता और संस्थागत मजबूती की आवश्यकता होती है। अमेरिका के लिए यह आत्ममंथन का क्षण है—और दुनिया के अन्य लोकतंत्रों के लिए भी एक चेतावनी कि राजनीतिक असहमति को हिंसा में बदलने से रोकना कितना आवश्यक है। यह घटना सिर्फ एक आपराधिक कृत्य नहीं, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था की गहरी खामियों को उजागर करती है। रिपोर्ट्स के अनुसार, हमलावर होटल में पहले से ठहरा हुआ था और सुरक्षा जांच में कई स्तरों पर चूक हुई—यहां तक कि कुछ क्षेत्रों में पर्याप्त निगरानी और मेटल डिटेक्टर जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं भी नहीं थीं।सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि हमलावर हथियारों के साथ कार्यक्रम स्थल के काफी करीब पहुंच गया और उसने एक सुरक्षा चौकी पर हमला किया।

एसी से सीधा धूप में जा रहे हो तो दिल, दिमाग, ब्लड वेसल्स, सबको लगेगा 'शॉक'

गर्मी से राहत पाने के लिए सभी घर में एयर कंडीशनर की सर्विस हो चुकी है और इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। एसी वाले कमरे से बाहर निकलने में हर किसी को आफत आ जाती है और अगर सीधा बाहर धूप में किसी काम से जाना पड़ जाए तो क्या ही कहने? लेकिन क्या आप जानते हैं कि एसी की ठंडी हवा से सीधा धूप में जाने पर क्या होता है? डॉ ने एसी से सीधा धूप में जाने पर दिमाग, दिल और रक्त वाहिकाओं पर पड़ने वाले असर के बारे में बताया है।





शरीर का इंटरनल थर्मोस्टेट सिस्टम

आपका शरीर 36.5 से लेकर 37.5°C के बीच एक अंदरुनी तापमान को बनाए रखता है। यह कंट्रोल सिस्टम दिमाग के छोटे से, मगर बहुत ताकतवर हिस्से द्वारा मैनेज किया जाता है, जिसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। जब आप एसी के ठंडे वातावरण से गर्मी में बाहर कदम रखते हैं तो शरीर अचानक से बाहरी तापमान में बढ़ोतरी को भांप लेता है। इसके तुरंत बाद हाइपोथैलेमस शरीर का ठंडा करने की प्रक्रिया शुरू कर देता है, जिसमें-

स्किन मे मौजूद ब्लड वेसल्स चौड़ी होने लगती हैं, जिसे वैसोडिलेशन कहते हैं

गर्मी बाहर निकालने के लिए स्वेट ग्लैंड्स काम करने लगती हैं

दिल की धड़कन धीरे से बढ़ जाती है

ये शारीरिक प्रतिक्रिया गर्म माहौल में आपको ठंडा होने में मदद करती हैं, मगर पूरी तरह एडजस्ट होने में कुछ मिनट का वक्त लगता है।

शरीर को क्यों होता है 'शॉक' जैसा एहसास

डॉक्टर के मुताबिक, शरीर को जो असहजता होती है, वो 'हीट शॉक' जैसा एहसास होता है, जो कि तापमान बदलने पर नर्वस सिस्टम की प्रतिक्रिया से होता है। आपकी स्किन के पास खास टेंप्रेचर सेंसर होते हैं, जो दिमाग को सिग्नल भेजते हैं। ठंड से गर्म माहौल में अचानक बदलाव आने से ये सेंसर ओवरस्टिम्युलेट हो जाते हैं। दिमाग को तेजी से एडजस्ट करना पड़ता है, जिसकी वजह से कुछ पल के लिए भारीपन या भ्रम जैसी स्थिति हो सकती है। यह एहसास आमतौर पर हानिरहित होता है, लेकिन धूप या बहुत गर्म माहौल की वजह से इंटेंस हो सकता है।

चक्कर आना और सिर घूमने की समस्या

ठंडे कमरे से सीधा धूप में जाने पर अक्सर सिर घूमने या चक्कर आने की शिकायत आमतौर पर देखी जाती है। ऐसा इसलिए होता है, क्योंकि आपकी रक्त वाहिकाएं अचानक से चौड़ी होने लगती हैं। थोड़े समय के लिए ब्लड प्रेशर गिर जाता है और दिमाग तक खून की सप्लाई कम पहुंचने लगती है। यह स्थिति अक्सर हल्की होती है, लेकिन डिहाइड्रेशन या ब्लड प्रेशर की दवा लेने पर थोड़ी ज्यादा प्रभावित कर सकती है।

हाइड्रेशन का काम

एक्सपर्ट बताती हैं कि एयर कंडीशनर वाले माहौल में ह्यूमिडिटी कम होती है, जिससे बॉडी में ड्राईनेस बढ़ती है। आप ऐसे माहौल में पसीना निकाले बिना भी बॉडी फ्लूइड खोते रहते हैं। फिर आप जब गर्मी में कदम रखते हैं तो तेजी से पसीना निकलना शुरू हो जाता है और फ्लूइड की कमी ज्यादा हो जाती है। अगर आप पहले से डिहाइड्रेटेड रहेंगे तो सिरदर्द, थकान और फोकस में कमी झेलनी पड़ सकती है।

गर्मी में सिरदर्द

आसपास के तापमान में अचानक बदलाव आने से कुछ लोगों में सिरदर्द और माइग्रेन का दर्द होना आम है। Cephalalgia जैसे जर्नल पर प्रकाशित रिसर्च बताती हैं कि एनवायरमेंटल चेंजेस में गर्मी बढ़ने जैसा बदलाव दिमाग के अंदर मौजूद पेन पाथवे को एक्टिवेट कर सकता है। आसान भाषा में समझें तो ऐसे बदलावों के प्रति दिमाग काफी संवेदनशील होता है। टेंप्रेचर में आया बड़ा बदलाव ट्रिगर की तरह काम करता है। माइग्रेन के मरीजों के अंदर यह समस्या ज्यादा आम देखी जाती है।

धूप से एसी में जाने पर क्या होता है?

अगर आप धूप या गर्मी से अचानक एसी के कमरे में जाएं तो भी शरीर पर प्रभाव पड़ता है। ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगती है, जिसे वैसोकंस्ट्रिक्शन कहते हैं। इसकी वजह से पसीने का उत्पादन कम हो जाता है, स्किन टेंप्रेचर तेजी से गिरता है और कुछ लोगों को कोल्ड हेडेक (ठंड के कारण होने वाला सिरदर्द), हल्की अकड़न और साइनस में दिक्कत हो सकती है। हालांकि, ये समस्याएं भी अस्थाई होती हैं और शरीर संतुलन प्राप्त करने के लिए कोशिश करने लगता है।

क्या बार-बार सर्दी-गर्मी होने से बीमार पड़ते हैं?

लोगों के बीच एक सामान्य मान्यता है कि एसी से गर्मी में बार-बार आने जाने से बीमारी होती है। हालांकि यह पूरी तरह ठीक नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक, अकेले तापमान में बदलाव आने से इंफेक्शन नहीं होता। इसका असल जिम्मेदार वायरस और बैक्टीरिया है। हालांकि, बार-बार ठंड-गर्मी में आने जाने से शरीर पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है और एनर्जी लेवल व कंफर्ट प्रभावित होता है। इससे कुछ लोगों को थकान की समस्या हो सकती है।

क्या शरीर खुद को ढाल लेता है?

मानव शरीर गर्मी के मुताबिक खुद को ढाल लेता है और इस प्रक्रिया को acclimatization कहते हैं। तापमान में नियमित होने वाले ऐसे बदलाव के बाद शरीर की पसीना उत्पादन करने की क्षमता माहौल के मुताबिक काम करने लगती है। दिल तनाव को झेलना सीख जाता है। आपको धूप में जाने पर कम परेशानी होने लगती है। लेकिन, लगातार एसी में रहने से यह प्रक्रिया प्रभावित भी हो सकती है।

किन टिप्स का रखें ध्यान?

एसी से धूप में जाने से पहले कुछ देर छाया में रहें।

एसी में रहने पर भी पर्याप्त पानी पीएं।

एसी का टेंप्रेचर बहुत कम ना रखें।

अगर चक्कर आ रहे हैं तो सावधान हो जाएं और शरीर को माहौल के मुताबिक ढलने का समय दें।

एयर कंडीशनर से धूप में जाने पर शरीर हर बार एक कॉम्प्लेक्स बैलेंसिंग प्रोसेस से गुजरता है। इस प्रक्रिया के दौरान आपका दिमाग, ब्लड वेसल्स और हाइड्रेशन स्टेटस एकसाथ काम करता है। अधिकतर लोगों में यह एडजस्टमेंट सेफ होती है। लेकिन अपने शरीर की प्रतिक्रिया पर अक्सर ध्यान देकर गंभीर स्थितियों से बचा जा सकता है।

चेहरे को चमकाएगा दूध, इन तरीकों से कर सकते हैं इसका इस्तेमाल

हर त्वचा का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अगर इस मौसम में सही तरह से त्वचा का ध्यान न रखा जाए तो कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं। इसकी वजह है कि कई जगहों का पारा 50 डिग्री पहुंच रहा है। ऐसे में लोगों की त्वचा धूप से जल रही है।जो लोग अपनी त्वचा का ध्यान नहीं रखते हैं उन्हें सनबर्न, रैशेज, खुजली, घमौरियों, मुंहासों जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ये परेशानियां इतना बढ़ जाती हैं कि डॉक्टर तक से सलाह ली जाती है। ऐसे में आप कच्चे दूध का इस्तेमाल करके अपनी त्वचा का ध्यान रख सकते हैं।



अगर आप दूध की मदद से अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं तो इस लेख में हम आपको इसके कुछ तरीके बताएंगे। कच्चे दूध का इस्तेमाल करके आप अपनी त्वचा की रंगत निखार सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आपको इसका तरीका बताते हैं।

दूध और शहद

अगर आप कच्चे दूध में शहद को मिलाकर अपनी त्वचा पर लगाएंगी तो इससे त्वचा में निखार आएगा। इसके साथ ही इसके इस्तेमाल से आपकी त्वचा खिल उठेगी। इसके लिए आपको बस एक कटोरी में दो चम्मच दूध लेकर उसमें थोड़ा सा शहद मिक्स करना है। अब इसे नियमित रूप से अपनी स्किन पर लगाएं। कुछ ही दिनों में आपको इसका असर दिखने लगेगा।

बेसन और दूध

इस मौसम में अपने चेहरे को साफ रखने के लिए आप दूध को बेसन में मिलाकर लगा सकते हैं। इसके लिए एक कटोरी में सबसे पहले बेसन लें। अब इसमें कच्चा दूध डालकर पेस्ट बना लें। इसे 15 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगाएं और फिर पानी से चेहरा धो लें। त्वचा की रंगत सुधारने में ये काफी मदद करेगा।

मुल्तानी मिट्टी और दूध

मुल्तानी मिट्टी तो हर किसी को सूट कर जाती है। ऐसे में आप दूध में इसे मिलाकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस कच्चे दूध में मुल्तानी मिट्टी डालकर इसका पेस्ट बनाना है और इसे चेहरे पर लगाना है। इससे आपकी त्वचा खिल उठेगी।

हल्दी और दूध

इन दोनों चीजों में पाए जाने वाले तत्व त्वचा को खिलाने का काम करते हैं। ऐसे में आप इन दोनों चीजों को मिक्स करके स्किन पर लगा सकते हैं। इस पेस्ट को बनाने के लिए आपको हल्दी सिर्फ एक चुटकी ही लेनी है। इसके इस्तेमाल से आपको त्वचा के दाग-धब्बों से भी छुटकारा मिलेगा।



ब्लैडर कैंसर के खतरे को छह गुना तक बढ़ा देती है ये आदत

कैंसर दुनियाभर में तेजी से बढ़ती बीमारी है, जिसके कारण हर साल लाखों लोगों की मौत हो जाती है। ब्लैडर यानी मूत्राशय के कैंसर के मामलों में भी वैश्विक स्तर पर उछाल देखा जा रहा है। ब्लैडर कैंसर, मूत्राशय की कोशिकाओं में शुरू होता है। अगर आपके पेशाब से खून आता है, पेशाब करने में दर्द होता है या फिर बार-बार पेशाब जाने की जरूरत महसूस होती है तो इसे ब्लैडर कैंसर का संकेत माना जा सकता है।

ब्लैडर कैंसर के बढ़ते जोखिमों और इसके कारणों को समझने के लिए किए गए अध्ययन में वैज्ञानिकों ने धूम्रपान को इसका प्रमुख जोखिम कारक माना है। विशेषज्ञों का कहना है कि हाल के वर्षों में निदान किए गए इस कैंसर के 50-60 फीसदी मामलों की प्रमुख वजह भी धूम्रपान है।

धूम्रपान के कारण खतरा

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं, धूम्रपान की आदत मूत्राशय के कैंसर के खतरे को छह गुना तक बढ़ देती है। सिगरेट पीने से मूत्र में हानिकारक रसायन जमा होने से मूत्राशय कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। जब आप धूम्रपान करते हैं, तो आपका शरीर धुएं में मौजूद रसायनों को संसाधित करता है और उनमें से कुछ को आपके मूत्र में उत्सर्जित करता है। ये हानिकारक रसायन आपके मूत्राशय की परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे आपके कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।

जोखिम कारकों को भी जानना जरूरी

धूम्रपान के कारण ब्लैडर कैंसर का जोखिम तो बढ़ता ही है इसके अलावा भी कई अन्य जोखिम कारक हैं जिनको लेकर सभी लोगों को गंभीरता से ध्यान देते रहने की जरूरत होती है। उम्र बढ़ने के साथ मूत्राशय कैंसर का जोखिम बढ़ जाता है, हालांकि यह किसी भी उम्र में हो सकता है।

इसके लक्षणों की पहचान?

स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कैंसर कोई भी हो, अगर इसके लक्षणों की समय पर पहचान होकर इलाज शुरू हो जाए तो कैंसर के फैलने का खतरा कम हो सकता है। अगर आपको लगता है कि आपके पेशाब का रंग कुछ समय से बदला दिख रहा है, उसमें खून आ रहा है तो शीघ्रता से डॉक्टर से मिलकर इसकी जांच करवाएं। पेशाब में होने वाली समस्याओं के साथ कुछ लोगों को अक्सर पीठ में दर्द की दिक्कत भी बनी रहती है।

ब्लैडर कैंसर के जोखिमों से बचाव

मूत्राशय कैंसर को रोकने का कोई सटीक तरीका नहीं है, फिर भी आप अपने जोखिम को कम करने में मदद के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं। अगर आप धूम्रपान करते हैं, तो इसे तुरंत छोड़ दें। धूम्रपान छोड़ने से आप इस कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम कर सकते हैं। धूम्रपान के अलावा जो लोग रसायनों के अधिक संपर्क में रहते हैं उनमें भी कैंसर विकसित होने का खतरा अधिक देखा जाता है।

आहार में विभिन्न प्रकार के रंगीन फलों और सब्जियों को शामिल करना शरीर को स्वस्थ रखने और कैंसर के खतरे से बचाव करने का एक तरीका हो सकता है। फलों और सब्जियों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट कैंसर के जोखिमों को कम करने में मदद कर सकते हैं।

क्या आपने खाई है कटहल की बिरयानी? ये है रेसिपी, बार-बार डिमांड करेंगे मेहमान

आजकल बहुत से लोग वेज खाने को पसंद करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें लगता है कि वेज में उतना मजा नहीं होता जितना नॉन-वेज डिशेज में होता है. खासकर बिरयानी जैसी रिच और खुशबूदार डिश हर किसी की फेवरेट है. ऐसे में कटहल की बिरयानी एक ऐसी डिश है जो टेस्ट में इतनी अच्छी होती है कि नॉन-वेज खाने वाले लोग भी इसे खाकर हैरान रह जाते हैं. कटहल की बनावट काफी हद तक मीट जैसी लगती है, इसलिए यह बिरयानी बिल्कुल स्पेशल बन जाती है. अगर घर पर कुछ खास बनाना हो, या मेहमानों को इम्प्रेस करना हो, तो यह रेसिपी आपके लिए बेस्ट है. तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि घर पर कटहल की बिरयानी कैसे बनाएं?

कटहल की बिरयानी बनाने के लिए क्या-क्या चीजें चाहिए?

कटहल बिरयानी बनाने के लिए आपको कुछ आसान लेकिन खुशबूदार सामग्री की जरूरत होती है, जो इस डिश के टेस्ट बढ़ाती हैं. इसमें मुख्य रूप से कटा हुआ कटहल और आधे पके



हुए चावल चाहिए होते हैं, जो बिरयानी का बेस बनाते हैं. इसके साथ ही प्याज, अदरक-लहसुन पेस्ट, हरी मिर्च और हरा धनिया, मसालों में धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला, साथ ही काजू, बादाम और केसर की जरूरत होती है.

घर पर कटहल की बिरयानी कैसे बनाएं?

1. घर पर कटहल की बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाही में तेल गर्म करें और कटे हुए प्याज को सुनहरा होने तक अच्छे से तल लें फिर इन्हें निकालकर अलग रख दें.

2. अब उसी कढ़ाही में थोड़ा तेल डालकर कटहल को अच्छे से भून लें, जब तक वह हल्का सुनहरा न हो जाए फिर इसे भी अलग निकाल लें.

3. अब काजू और बादाम को हल्का सा तल लें जिससे उनका टेस्ट और बढ़ जाए.

4. अब कढ़ाही में थोड़ा तेल डालें और उसमें भुना हुआ कटहल डालें. इसके बाद तले हुए प्याज मिलाएं. अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च, हरी मिर्च, केसर और नमक डालें. साथ ही सबको अच्छे से मिक्स करें फिर अदरक-लहसुन पेस्ट और नींबू का रस डालकर मिलाएं.

5. अब इसमें थोड़ा पानी डालें और धीमी आंच पर 15-20 मिनट तक पकने दें, जिससे मसाला अच्छी तरह से तैयार हो जाए.

6. अब एक पैन लें और उसमें सबसे पहले चावल की एक लेयर डालें फिर कटहल मसाले की लेयर, अब दोबारा चावल और फिर मसाला, लास्ट में ऊपर से चावल की लेयर डालें.

7. अब ऊपर से केसर, काजू और बादाम, तला हुआ प्याज डालें. अब पैन को ढक कर 15-20 मिनट धीमी आंच पर पकाएं.

8. जब बिरयानी तैयार हो जाए, तो ऊपर से हरा धनिया डालकर गरमा-गरम सर्व करें.

कान में खुजली सर्दी, फ्लू, एलर्जी का लक्षण कब बनता है जोखिम

कान में खुजली एक आम समस्या है, जिसे कई लोग गैरजरूरी मानकर अनदेखा कर देते हैं। कुछ मामलों में यह एलर्जी या अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन (URI) जैसी समस्याओं का शुरुआती संकेत हो सकता है। कई लोग ये मानते हैं कि कान में खुजली होना सर्दी, फ्लू या एलर्जी का शुरुआती संकेत है, लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं।

कान में खुजली को अक्सर अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन (URI) यानी नाक, गले और साइनस का वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन का शुरुआती संकेत मान लिया जाता है। इसमें सर्दी-जुकाम, गले में खराश, नाक बहना और हल्की खांसी जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। सर्दी या फ्लू के दौरान अपर रेस्पिरेटरी एरिया में सूजन आ जाती है।

कान, नाक और गला आपस में जुड़े होते हैं, इसलिए यह सूजन ईयर कैनाल या यूस्टेशियन ट्यूब तक फैल सकती है। इससे हल्की खुजली या कान में भारीपन महसूस हो सकता है। एलर्जी की स्थिति में शरीर हिस्टामाइन छोड़ता है, जिससे नाक, गले और कान के अंदर भी खुजली होती है।

कानों में खुजली कभी-कभी सर्दी या एलर्जी का शुरुआती संकेत हो सकता है, लेकिन हर केस में इसका कारण एक जैसा नहीं हो सकता। इस लेख में हम कान में खुजली के कारण और बचने के उपाय बता रहे हैं।

कान में खुजली के कारण

कान में खुजली सिर्फ नाक, गले और साइनस के वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण नहीं होती इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। आमतौर पर कान में खुजली के ये कारण हो सकते हैं-

ईयर कैनाल में सूखापन- कान का मैल (cerumen) ईयर कैनाल यानी कान की नलिका को नम रखने और इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है। जब यह मैल ज्यादा सफाई या स्किन प्रॉब्लम के कारण कम हो जाता है, तो कान के अंदर की त्वचा सूख जाती है और उसमें खुजली होने लगती है।

फंगल इन्फेक्शन- जिन जगहों पर ह्यूमिडिटी और गर्मी ज्यादा होती है वहां के लोगों में कान में खुजली की समस्या हो सकती है। ऐसी जगहों के लोग गर्मी से राहत पाने के लिए स्विमिंग करते हैं, जिससे कान में पानी जाने की संभावना बढ़ जाती है। इससे कान में खुजली के साथ बेचैनी, डिस्चार्ज या दुर्गंध भी आ सकती है।

एलर्जी- ये भी कान में खुजली का एक प्रमुख कारण है। धूल, पराग, हेयर प्रोडक्टस के संपर्क में आने या लंबे समय तक ईयरफोन और हियरिंग एड्स का उपयोग



करने से भी कान की नलिका में जलन और खुजली हो सकती है।

कॉटन बड्स का उपयोग- बार-बार कॉटन बड्स का उपयोग करना या कान में कोई वस्तु डालना अंदर की नाजुक त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा करने से कान में खुजली, जलन और कभी-कभी इन्फेक्शन भी हो सकता है।

कान में खुजली से बचने के लिए क्या करें ?

खुजली होने पर कॉटन बड्स या कोई अन्य चीज कान में डालना हानिकारक हो सकता है। इससे कानों में चोट या इन्फेक्शन का जोखिम बढ़ सकता है। अगर एलर्जी के कारण कान में खुजली हो रही है तो ऐसी चीजों से दूर रहें। कानों में खुजली से बचने के लिए ये तरीके अपनाए जा सकते हैं-

कानों को सूखा रखें, खासकर नहाने या तैरने के बाद

कान के बाहरी हिस्से को साफ तौलिए से पोंछें

ईयरफोन या ईयरबड्स का इस्तेमाल कम करें

एलर्जी पैदा करने वाली चीजों से बचें

कानों के लिए कौन सी आदतें हानिकारक ?

कई लोग अनजाने में गलत आदतें अपनाकर कान में खुजली की समस्या को बढ़ा देते हैं। इससे कान की प्राकृतिक सुरक्षा हटती है, स्किन को नुकसान पहुंचता है और इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। कानों की सुरक्षा के लिए ये आदतें हानिकारक हैं-

बार-बार उंगलियों से कान खुजलाना

कान में तेल या अन्य चीजें डालना

एक्सपर्ट से सलाह लिए बिना खुद दवा या ईयर ड्रॉप्स का उपयोग करना

कान साफ करने के लिए कॉटन बड्स, पिन, चाबी या किसी नुकीली चीज का इस्तेमाल करना

कानों के लिए कौन सी स्थितियां नुकसानदायक?

कानों में कभी-कभार खुजली होना आम बात है, लेकिन खुजली लगातार बढ़ने लगे तो ये नॉर्मल नहीं है। निम्नलिखित लक्षण दिखाई दें तो उन्हें नजरअंदाज न करें और कानों की जांच कराएं-

कानों में लगातार खुजली

कान बंद होने का एहसास

कानों में दर्द या जलन

कान के आसपास सूजन

सुनने में परेशानी

कान बहना

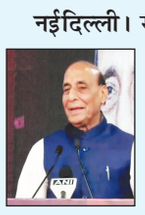
कानों में खुजली को नजरअंदाज न करें

कई बार कानों में खुजली मामूली परेशानी लग सकती है, लेकिन लापरवाही के कारण समस्या बढ़ सकती है। कानों को सुरक्षित रखने के लिए उनकी अच्छी तरह सफाई करें, हानिकारक आदतों से बचें, खुजली और अन्य लक्षणों पर ध्यान दें। खुजली या अन्य कोई समस्या बढ़ने लगे तो तुरंत जांच कराएं।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

हमने अपनी शर्तों पर रोका था ऑपरेशन सिंदूर : रक्षा मंत्री

नईदिल्ली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिस तीखे अंदाज में पाकिस्तान और आतंकवाद को ललकारा, वह स्पष्ट चेतावनी थी। उन्होंने साफ कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने अपनी शर्तों पर स्वेच्छा से रोका था। राजनाथ सिंह ने दो टूक कहा कि अगर जरूरत पड़ती तो भारत लंबी जंग के लिए पूरी तरह तैयार था और आज भी है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि देश के पास अचानक जरूरत पड़ने पर अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाने की क्षमता है, जो पहले से कहीं अधिक मजबूत हो चुकी है। उन्होंने आतंकवाद को लेकर भारत की नई नीति को बेहद साफ शब्दों में रखते हुए कहा कि अब आतंकवाद और उसे पालने पोसने वालों में कोई फर्क नहीं किया जाएगा। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की शून्य सहनशीलता नीति ने भारत को नई दिशा दी है।



कर्नाटक में फिलहाल मुख्यमंत्री बदलने का सवाल ही नहीं: खरगे

बेंगलूरू। कर्नाटक में जारी बयानबाजी के बीच नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं तेज थीं, लेकिन एक बार फिर डीके शिवकुमार की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कर्नाटक में सीएम बदलने की संभावनाओं को सिरे से खारिज कर दिया है। मल्लिकार्जुन खरगे ने गुरुवार को कहा कि कर्नाटक में फिलहाल मुख्यमंत्री बदलने का कोई सवाल नहीं है और राज्य में नेतृत्व का मुद्दा जल्द सुलझा लिया जाएगा। खरगे का यह बयान ऐसे समय आया है जब पार्टी और राजनीतिक हलकों में यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि जब 4 मई को चार राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो जाएंगे तो उसके में नेतृत्व परिवर्तन और कैबिनेट फेरबदल पर फैसला हो सकता है। डीके शिवकुमार और उनके भाई और पूर्व सांसद डीके सुरेश ने हाल ही में दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से मुलाकात भी की थी। जिसके बाद राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं जोर पकड़ गईं थीं।



पवन खेड़ा की जमानत याचिका पर असम पुलिस का कड़ा विरोध

नईदिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर तीखी बहस हुई। असम पुलिस ने खेड़ा की याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए उन पर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी, रिंकी भुइयां सरमा के पासपोर्ट के साथ छेड़छाड़ और जालसाजी करने का गंभीर आरोप लगाया है। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस एएस चांदुरकर की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। पुलिस ने कहा कि खेड़ा ने जो किया वह एक गैर-ज़मानती अपराध है और इस बात की जांच होनी चाहिए कि उन्होंने दस्तावेज़ों में जालसाज़ी कैसे की। असम पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि खेड़ा ने सरमा की पत्नी पर ये आरोप तब लगाए, जब विधानसभा चुनाव चल रहे थे। उन्होंने कहा कि खेड़ा ने रिंकी की तस्वीरें दिखाईं और नकली पासपोर्ट पेश किए।



आप के कई विधायक भाजपा में जाएंगे : कांग्रेस सांसद

चंडीगढ़। गुरदासपुर से कांग्रेसी सांसद एवं पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा ने दावा किया है कि पंजाब सरकार संकट में है और आने वाले समय में सूबे में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि आप के कई विधायक भाजपा के संपर्क में हैं और पार्टी छोड़ने के लिए सही समय का इंतजार कर रहे हैं। रंधावा ने स्पष्ट किया कि पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी और उनके समेत चार कांग्रेसी सांसदों के भी भाजपा में संपर्क होने की अफवाह फैलाई गई थी मगर मैं विश्वास से बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का कोई भी मौजूद सांसद और विधायक पार्टी छोड़ने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी में उथल-पुथल की स्थिति जरूर चल रही है। रंधावा ने कहा कि मुझसे किसी ने संपर्क नहीं किया। आप के राज्यसभा सांसदों को गद्दार कहने पर रंधावा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गद्दारों ने गद्दारों के साथ ही गद्दारी की है क्योंकि आम आदमी पार्टी में भी बहुत से नेता ऐसे हैं जो पहले शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस में थे।



बंगाल में मतदान खत्म होते ही आई-पैक निदेशक को जमानत

कोलकाता/नई दिल्ली। आई-पैक निदेशक विनेश चंदेल गिरफ्तार को मतदान से ठीक पहले गिरफ्तार किया गया था। मतदान समाप्त होते ही उन्हें जमानत मिल गई, जो कि महत्वपूर्ण घटना मानी जा रही है। उन्हें केंद्रीय जांच निदेशालय (ईडी) ने 13 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। उन पर वित्तीय धोखाधड़ी और विभिन्न प्रकार के बेहिसाब लेन-देन का आरोप है। इसके अलावा, विनेश चंदेल पर विभिन्न स्थानों से धन लेकर हवाला के माध्यम से विदेश भेजने का भी आरोप है। हालांकि, इस बार दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। जानकारी के अनुसार, केंद्रीय जांच एजेंसी (ईडी) ने चंदेल की जमानत का विरोध नहीं किया। विनेश चंदेल ने मंगलवार को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में अंतरिम जमानत याचिका दायर की थी। उन्होंने अदालत को बताया कि उनकी मां स्मृतिभ्रंश से पीड़ित हैं। घर में उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए।



विधानसभा के विशेष सत्र में विपक्ष पर बरसे यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

गेस्ट हाउस कांड याद दिलाकर सपा-कांग्रेस को घेरा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष, विशेषकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर कड़ा हमला बोला। महिला सशक्तिकरण के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्षी दलों ने हमेशा महिलाओं की गरिमा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी योजनाओं का विरोध किया है। उन्होंने संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष के रवैये को दोहरा करार दिया।

मुख्यमंत्री ने सदन में इंडिया गठबंधन की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए उठाए गए हर प्रगतिशील कदम में विपक्ष ने अड़ंगा लगाया है।

संसदीय आचरण: योगी आदित्यनाथ ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर हुई चर्चा का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी विपक्षी दलों का नकारात्मक रवैया पूरे देश ने देखा।

अस्थिरता का आरोप: उन्होंने कहा कि विपक्ष विकास की बात तो करता है, लेकिन जब सदन में ठोस प्रस्ताव आते हैं, तो वे अपनी राजनीति चमकाने के लिए उनका विरोध करते हैं।

उन्होंने कहा, महिलाओं के उत्थान, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए उठाए गए किसी भी प्रगतिशील कदम का विपक्षी पार्टियों ने हमेशा विरोध किया है। उन्होंने संसद में हुई पिछली बहसों का भी ज़िक्र किया और दावा किया कि लोकसभा में चर्चा के दौरान भी ऐसा ही रवैया देखने को मिला था।

महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी (सपा) पर हमला बोलते हुए सीएम ने 1995 के स्टेट गेस्ट हाउस कांड% का भी ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि यह घटना विपक्षी पार्टी के पिछले आचरण की याद दिलाती है। योगी आदित्यनाथ ने मायावती से जुड़ी उस घटना को याद किया, जब 1995 में



राजनीतिक तनाव के दौरान एक स्टेट गेस्ट हाउस में कथित तौर पर उन पर हमला किया गया था।

उन्होंने कहा, हर किसी को 1995 की वह घटना याद है, जब राज्य की पहली दलित मुख्यमंत्री को गेस्ट हाउस में हमले का सामना करना पड़ा था। यह समाजवादी पार्टी के आचरण को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उस समय भाजपा ने मायावती का समर्थन करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप किया था। उन्होंने दिवंगत भाजपा नेता ब्रह्म दत्त द्विवेदी का ज़िक्र करते हुए दावा किया कि उस घटना के दौरान उनकी सुरक्षा करने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी।

योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की गरिमा को लेकर विपक्ष के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस तरह की पिछली घटनाएं उनके रिकॉर्ड को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करती हैं। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं, और इसे महिलाओं के सम्मान से जुड़े मुद्दों की एक लंबी सूची बताया।

योगी आदित्यनाथ ने जन स्वास्थ्य प्रयासों, विशेष रूप से एन्सेफलाइटिस जैसी बीमारियों के खिलाफ लड़ाई के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में एन्सेफलाइटिस के मामले बड़ी संख्या में सामने आते थे, लेकिन पिछली सरकारें इसे नियंत्रित करने में नाकाम रही थीं। उन्होंने कहा, आपके ज़िलों में एन्सेफ़लाइटिस की वजह से सबसे ज़्यादा मौतें होती थीं। आप कुछ नहीं कर पाए। आज, डबल-इंजन सरकार के तहत, उत्तर प्रदेश में एन्सेफ़लाइटिस से कोई मौत नहीं होती।

मुख्यमंत्री ने पिछली ग्रामीण स्थितियों के बारे में भी कड़े बयान दिए, और कहा कि पहले गाँवों में महिलाओं को असुरक्षित स्थितियों का सामना करना पड़ता था, खासकर शाम के समय। उन्होंने दावा किया कि साफ़-सफ़ाई की कमी की वजह से महिलाओं को असुरक्षित स्थितियों में जाना पड़ता था और सार्वजनिक जगहों पर छेड़छाड़ की घटनाएँ होती थीं।

उन्होंने आगे कहा कि स्वच्छ भारत मिशन लागू होने के साथ ही यह स्थिति बदल गई है, जिसका मुख्य ज़ोर ग्रामीण इलाकों में शौचालय बनाने और साफ़-सफ़ाई को बेहतर बनाने पर था।

योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के व्यवहार की भी आलोचना की, और कहा कि उनका रुख़ मंच के हिसाब से बदलता रहता है। उन्होंने कहा, संसद में और इस सदन में आपका व्यवहार पूरी तरह से अलग होता है। आप जिस तरह से रंग बदलते हैं, उसे देखकर तो गिरगिट भी शर्मा जाए।

उन्होंने आगे कहा कि जहाँ एक तरफ़ विपक्षी पार्टियाँ अक्सर विकास का समर्थन करने का दावा करती हैं, वहीं सदन में जब ऐसे ही प्रस्ताव पेश किए जाते हैं, तो वे उनका विरोध करती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और स्वास्थ्य सरकारी नीतियों के केंद्र में हैं, और उन्होंने बड़े पैमाने पर सुधार लाने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई राष्ट्रीय पहलों को दिया।

जम्मू से श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारम्भ

उमर अब्दुल्ला ने पीएम मोदी का जताया आभार

श्रीनगर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जम्मू और श्रीनगर के बीच 20-कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह केंद्र शासित प्रदेश की दोनों राजधानियों के बीच पहली सीधी ट्रेन सेवा है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री जितेन्द्र सिंह भी इस दौरान मौजूद थे। जम्मू और श्रीनगर के बीच सीधी ट्रेन सेवा से यात्रा का समय कम होगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हम आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 6 जून 2025 को कटरा और श्रीनगर के बीच पहली सीधी ट्रेन सेवा का उद्घाटन किया था। अब इस सेवा को जम्मू तवी रेलवे स्टेशन तक विस्तारित किया जा रहा है।

लगभग 43,780 करोड़ रुपये की रेल परियोजना पर काम 1990 के दशक के अंत में शुरू हुआ था और अक्टूबर 2008 में कश्मीर घाटी में पहली ट्रेन चली थी। एक अधिकारी ने कहा, आधुनिक 20-कोच वाली वंदे भारत ट्रेन जम्मू तवी से अपनी पहली यात्रा शुरू करेगी, जो श्रीनगर तक चलेगी। यह घाटी के चुनौतीपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रों को जोड़ेगी। अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-श्रीनगर सेवा की शुरुआत से पहले, मंगलवार को



जम्मू से श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन तक वंदे भारत का संचालन परीक्षण किया गया था। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस और 20 कोच वाली प्रारंभिक वंदे भारत ट्रेन कुल 267 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।

हम आपको बता दें कि जम्मू-श्रीनगर ट्रेन सेवा दो मई से शुरू करने की योजना है। यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलेगी। मंगलवार को इस मार्ग पर कोई ट्रेन सेवा नहीं होगी। वरिष्ठ विभागीय वाणिज्यिक प्रबंधक उचित सिंघल ने कहा, स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके निर्मित यह वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों को एक विश्वस्तरीय यात्रा अनुभव प्रदान करेगी।

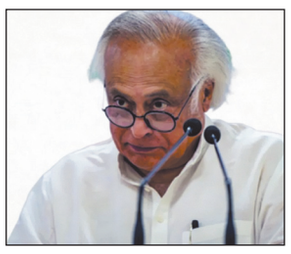
वहीं इस ट्रेन सेवा के शुरू होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैं आज इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं। आज वाकई हमने जम्मू को रेल के माध्यम से कश्मीर से जोड़ा है... इस 8 बोगी वाली रेल को 20 बोगी वाली रेल में तब्दील किया गया है, यह बहुत बड़ी बात है। इससे बहुत लोग सफर कर पाएंगे।

जातीय सर्वे को टालना चाहते हैं पीएम मोदी : कांग्रेस

नई दिल्ली। कांग्रेस ने गुरुवार को कहा कि सरकार द्वारा जातीय जनगणना की घोषणा किए एक साल पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि यह प्रक्रिया कैसे पूरी की जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जातीय सर्वे को टालना चाहते हैं। कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि आज ही के दिन एक साल पहले मोदी सरकार ने आगामी जनगणना में जातीय गणना को भी शामिल करने की घोषणा की थी।

जयराम रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री के नाटकीय यू-टर्न की समयरेखा ये है कि 21 जुलाई 2021 को लोकसभा में एक भाजपा सांसद के सवाल के जवाब में गृह मंत्री ने कहा था कि सरकार ने नीति के तौर पर जातिवार जनसंख्या की गणना नहीं करने का फैसला किया है। इसके बाद 21 सितंबर 2021 को मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा कि जातिवार जनगणना के लिए अदालत का कोई भी निर्देश सरकार के नीति-निर्णय में हस्तक्षेप के समान होगा।

कांग्रेस नेता ने यह भी उल्लेख किया कि 16 अप्रैल 2023 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना कराने की मांग की थी। हालांकि 28 अप्रैल 2024 को एक



इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने कहा था कि जातीय जनगणना की मांग अर्बन नक्सल की सोच को दर्शाती है। जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री को इस टिप्पणी के लिए कांग्रेस नेतृत्व से माफी मांगनी चाहिए और साथ ही देश की जनता को यह भी बताना चाहिए कि 30 अप्रैल 2025 को जातीय जनगणना की घोषणा करते समय उनकी सोच कथित अर्बन नक्सल के विचार से कैसे प्रभावित हुई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पोस्ट में लिखा, पूरा एक साल बीत चुका है, लेकिन अब तक ये साफ नहीं है कि जातीय गणना कैसे की जाएगी। विपक्षी दलों, राज्य सरकारों और इस विषय के विशेषज्ञों से कोई बातचीत नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने 5 मई 2025 को इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को फिर पत्र लिखा था, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि उस पत्र में उठाए गए मुद्दे आज भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने दावा किया कि हाल ही में समाप्त हुए विशेष सत्र के बाद यह और स्पष्ट हो गया है कि प्रधानमंत्री जातीय जनगणना को टालने की मंशा रखते हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच भिड़ंत आज

जयपुर। दिल्ली कैपिटल्स के पास पिछले कुछ मैच के निराशाजनक नतीजों पर विचार के लिए अधिक समय नहीं है क्योंकि टीम को शुक्रवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग मैच में आत्मविश्वास से भरी राजस्थान रॉयल्स का सामना करना है।



अक्षर पटेल की अगुआई वाली दिल्ली की टीम के लिए यह सत्र काफी मुश्किलों भरा रहा है। पिछले दो मैच में टीम के प्रदर्शन में काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिला। एक तरफ उन्होंने 250 से अधिक का स्कोर बनाया लेकिन विरोधी टीम ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए उस लक्ष्य को हासिल कर लिया वहीं दूसरी तरफ वे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ सिर्फ 75 रन पर ऑल आउट हो गए।

इसके अलावा इस महीने की शुरुआत में गुजरात टाइटंस के खिलाफ मिली एक रन की हार ने दिल्ली को भावनात्मक रूप से काफी चोट पहुंचाई है। तीन जीत और चार हार के साथ वे अंक तालिका में सातवें स्थान पर हैं और उन्हें जल्द ही अपने प्रदर्शन में सुधार की जरूरत है। दिल्ली के लिए सबसे बड़ी चिंता उनकी बल्लेबाजी में निरंतरता की कमी रही है। लोकेश राहुल, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिजवी जैसे खिलाड़ियों ने बीच-बीच में अच्छा योगदान दिया है लेकिन पूरी टीम मिलकर एक साथ अच्छा प्रदर्शन करने में नाकाम रही है।

पिछले मैच में अभिषेक पोरेल ने 'इम्पैक्ट प्लेयर' के तौर पर बल्लेबाजी करते हुए टीम को शर्मनाक स्कोर पर ऑल आउट होने से बचाया था। यह उस मैच के कुछ सकारात्मक पहलुओं में से एक था। ऐसे में टीम प्रबंधन उन्हें एकादश में मौका देने के बारे में सोच सकता है। गेंदबाजी के मोर्चे पर कुछ अच्छी खबरें भी हैं। तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क एक मई से खेलने के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से मंजूरी मिलने के बाद टीम में वापसी करने के लिए तैयार हैं।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 582 अंक गिरा निफ्टी 23997 पर बंद

नईदिल्ली। वैश्विक बाजारों में कमजोर रुख के साथ भारतीय शेयर बाजारों में भी गुरुवार (30 अप्रैल) को गिरावट में बंद हुए। कच्चे तेल की कीमतों में भारी तेजी और डॉलर के मुकाबले रुपये में गिरावट का बाजार के सेंटीमेंट्स पर नेगेटिव असर पड़ा। तीस शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 77,014 पर खुला। बुधवार को यह 77,496 पर बंद हुआ था। कारोबार के दौरान यह 1,200 अंक से भी ज्यादा गिर गया था। अंत में कुछ रिकवरी दिखाते हुए 582.86 अंक या 0.75 फीसदी की गिरावट लेकर 76,913.50 पर बंद हुआ। इसी तरह, नैशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 23,996 पर खुला और इसी के साथ फिर 24 हजार के लेवल के नीचे चला गया। जबकि इंट्रा-डे ट्रेड में यह 23,796 तक फिसल गया था। अंत में 180.10 अंक या 0.74 फीसदी गिरकर 23,997 पर बंद हुआ।

ब्रेंट क्रूड 125 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंचा

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर भारी तेजी दर्ज की गई है। गुरुवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल उछलकर 120 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर पहुंच गया है, जो वर्ष 2022 के बाद का सबसे उच्चतम स्तर है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष में गतिरोध और ईरानी बंदरगाहों व निर्यात पर अमेरिका की लंबी नाकेबंदी की चिंताओं के कारण वैश्विक तेल आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका से यह भारी उछाल आया है। इस ऊर्जा संकट के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ता तनाव एक प्रमुख कारण है। रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें होर्मुज़ जलडमरूमध्य को फिर से खोलने की पेशकश की गई थी; ट्रंप का स्पष्ट कहना है कि जब तक कोई व्यापक परमाणु समझौता नहीं हो जाता, तब तक रोक जारी रहेगी।

वारी एनर्जीज का चौथी तिमाही में मुनाफा 75 प्रतिशत बढ़ा

नई दिल्ली। वारी एनर्जीज लिमिटेड का 2025-26 की चौथी तिमाही में एकीकृत शुद्ध लाभ करीब 75 प्रतिशत की बढ़त के साथ 1,126 करोड़ रुपए रहा। कंपनी का 2024-25 की चौथी (जनवरी-मार्च) तिमाही में मुनाफा 644.47 करोड़ रुपए रहा था। वारी एनर्जीज ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि जनवरी-मार्च तिमाही के दौरान कंपनी की कुल आय दोगुनी से अधिक होकर 8,659.98 करोड़ रुपए रही जो 2024-25 की समान तिमाही में 4,140.92 करोड़ रुपए थी। समूचे वित्त वर्ष 2025-26 में वारी एनर्जीज लिमिटेड का शुद्ध लाभ बढ़कर 3,884.15 करोड़ रुपए हो गया जो 2024-25 में 1,928.13 करोड़ रुपए था। कंपनी के निदेशक मंडल ने 31 मार्च 2026 को समाप्त वर्ष के लिए 10 रुपए अंकित मूल्य वाले प्रति शेयर पर दो रुपए (20 प्रतिशत) का अंतिम लाभांश देने की सिफारिश की है।

देश में एफडीआई 90 अरब डॉलर के पार रहने की उम्मीद

नई दिल्ली। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बीते वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल-फरवरी के दौरान 88 अरब डॉलर से अधिक रहा। समूचे वित्त वर्ष में इसके 90 अरब डॉलर के पार पहुंच जाने की उम्मीद है। भाटिया ने कहा कि सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने के लिए कई उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि बीते वित्त वर्ष में अप्रैल से फरवरी के दौरान निवेश 88 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और पूरे वित्त वर्ष 2025-26 में इसके 90 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक रहने का अनुमान है। सचिव ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते और तेजी से बढ़ती आर्थिक वृद्धि देश को अच्छा निवेश आकर्षित करने में मदद कर रही है।

भारत के लिए सस्ते तेल का रास्ता कैसे खुल रहा है?

अभिनय आकाश

दुबई से खबर आई है जो पूरे ग्लोबल एनर्जी मार्केट को हिला सकती है। यूनाइटेड अरब अमीरात ने ऐलान किया है कि वो ओपक छोड़ रहा है और सिर्फ ओपक नहीं ओपक प्लस भी छोड़ रहा है। यह कोई मामूली खबर नहीं है। यूईई 1967 से यानी 1976 से ओपक का मेंबर है। यानी लगभग 60 साल से वह दुनिया का सातवां सबसे बड़ा तेल प्रोड्यूसर है। ओपक के अंदर सऊदी अरब इराक के बाद तीसरा सबसे बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है यूएई। माना क्या जाता है? है यह सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तीसरा। ऐसा देश अगर इस ग्रुप को छोड़ रहा है तो यह एक ऐसी दरार है जो सालों तक भरी नहीं जा सकेगी। यूएई के इस फैसले के बाद इंटरनेशनल ऑयल ट्रेड का क्या होगा? वो एक अलग सवाल है। लेकिन इस फैसले के पीछे कहानी सिर्फ तेल की नहीं है। इसमें ईरान के साथ चल रही जंग है, अमेरिका का दबाव है और साथ ही सऊदी अरब और यूएई के बीच की पुरानी खटास का भी योगदान है। लेकिन इन सब के बीच एक दिलचस्प बात ये है कि दो दिन पहले एनएसए अजीत डोभाल यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नहयान से मिलकर आए थे। इसके साथ काफी चर्चा हो रही है। क्योंकि चर्चा भारत की यूएई के साथ एनर्जी सिक्योरिटी पर हुई थी। तो डेफिनेटली अगर यूएई इतना बड़ा फैसला लेने वाला होगा तो इस पर भी चर्चा हुई होगी और भारत की तरफ से भी कुछ ना कुछ तो जरूर इस पर कहा गया होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यूएई के इस फैसले का असर भारत पर अच्छा पड़ने वाला है। भारत के यूएई के बेहतरीन संबंध हैं। इस फैसले से पहले ही भारत ने बड़ी रणनीतिक



पहल करते हुए अपने हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को यूएई के दौरे पर भेजा था। यूएई से बातचीत में रणनीतिक संबंधों को बढ़ाए जाने के साथ-साथ एनर्जी सिक्योरिटी पर भी सार्थक चर्चा हुई थी। यूएई के इंडस्ट्री और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी मंत्री सुल्तान अहमद अल जबेर भी एक प्रतिनिधिमंडल के साथ इस साल की शुरुआत में दिल्ली के दौरे पर आए थे। उस वक्त उन्होंने यह ऐलान किया था-ग्लोबल एनर्जी की मांग के मामले में भारत अब निर्णायक मुखिया है। भारत के एनएसए अजीत डोभाल ने हाल ही में अबुधाबी में थे। उन्होंने यूएई के एनर्जी मिनिस्टर और राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, डोभाल ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायेद अल नहयान से मुलाकात की थी। इस दौरान भारत और यूएई के बीच व्यापक रणनीतिक भागीदारी को और गहरा करने और क्षेत्रीय हालात व साझा हितों के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के उपायों, इलाके के हालात और आपसी लाभ के दूसरे मुद्दों पर चर्चा की थी।

ओपैक क्या है : ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। हिंदी में कहें तो तेल निर्यात करने वाले देशों का संगठन या समूह। इसकी जो शुरुआत थी वो हुई थी 1960 में बगदाद में जब पांच देशों ने मिलकर इसे बनाया था। ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला इसमें शामिल थे। इन देशों का मकसद एक था तेल की कीमतें कैसे तय हो, कितना तेल निकाला जाए, कितना प्रोड्यूस किया जाए, यह फैसला अमेरिका और यूरोप की बड़ी कंपनियों के हाथ से वापस लेकर खुद करना। यूएई 1967 यानी 1976 में इसमें शामिल हुआ। आज ओपेक में 12 देश हैं और दुनिया का करीब 38त्न तेल यही ग्रुप प्रोड्यूस करता है।

ओपक प्लस क्या है? : 2016 के आसपास ओपेक ने रूस जैसे कुछ बड़े गैर ओपेक तेल उत्पादक देशों के साथ एक एक्सटेंडेड अलायंस बनाया था। इसी को कहा जाता है ओपेक प्लस। यह ग्रुप मिलकर तय करता है कि दुनिया में कितना तेल बेचा जाएगा ताकि कीमतें ना बहुत ज्यादा गिरे और ना बहुत ज्यादा चढ़े। यूएई ने अब इन देशों से नाता तोड़ने का फैसला कर लिया है।



आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.